दैनिक
सच्चे दिन

वर्ष-06 | अंक-202 | प्रात:कालीन हिन्दी दैनिक | भोपाल, सोमवार 26 अक्टूबर 2026 | पृष्ठ-8 | मूल्य-1 रुपये

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शहडोल में किया 9.77 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को 22.89 करोड़ बोनस राशि का वितरण

हाथियों के उत्पात से क्षतिग्रस्त मकान की जगह लोगों को पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि तेंदूपत्ता संग्रहण लाखों वनवासी परिवारों की आजीविका का माध्यम है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि मेहनतकश परिवारों को उन हक का पूरा लाभ समय पर मिले। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रविवार को शहडोल संभागीय मुख्यालय में हुए एक भव्य कार्यक्रम में तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2024 के 9 लाख 77 हजार 696 पात्र संग्राहकों को 22 करोड़ 89 लाख रुपये से अधिक की प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि (तेंदूपत्ता बोनस) का वितरण किया। कार्यक्रम में पांच जिलों (शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सतना एवं सीधी) के अधीन छह जिला वनोपज सहकारी यूनियनों के हजारों तेंदूपत्ता एवं अन्य वनोपज संग्राहकों ने सहभागिता की।



किसानों को भावांतर और लाड़ली बहनों को मिल रहा संबल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार जनकल्याण, विकास और समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस वितरण से लेकर किसानों, लाड़ली बहनों, विद्यार्थियों और जनजातीय परिवारों के हित में कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की प्रमुख घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि शहडोल में अत्याधुनिक सुविधायुक्त एक इंडोर स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स बनाया जायेगा। जयसिंहनगर विस क्षेत्र के गोहपारू में शहडोल-रीवा मुख्य मार्ग से महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र तक सड़क निर्माण कराया जायेगा। मुख्यमंत्री ने शहडोल में गीता भवन का निर्माण करने तथा निजी निवेश एवं सहभागिता से यहां एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोले जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने शहडोल में नये महाविद्यालय की मांग के संबंध में कहा कि यहां के शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय के कालेज को अब कामन कर दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उमरिया जिले में जीर्ण-शीर्ण हो चुके एक आवागमन मार्ग पर एमपीआरडीसी द्वारा एक नई सड़क बनाई जायेगी।

सड़क और गीता भवन की सौगात

मुख्यमंत्री ने शहडोल के विकास से जुड़े स्थानीय सुझावों पर नगर तहसील क्षेत्र में शहडोल-रीवा मुख्य मार्ग से महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र तक सड़क निर्माण की घोषणा की। उन्होंने शहडोल में सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों के लिए गीता भवन के निर्माण की घोषणा भी की।मुख्यमंत्री ने कहा कि शहडोल में उच्च शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है, ताकि स्थानीय विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही उन्होंने महाविद्यालय में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा आगामी शैक्षणिक सत्र में एक नए प्रायवेट विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर की दो टूक

आतंकवाद को पालने वाले देशों पर कसे शिकंजा



नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने आतंकवाद और दुनिया में चल रहे संघर्षों को लेकर कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली में आयोजित 'चिन्मय अमृत महोत्सव ग्लोबल सम्मेलन' में उन्होंने कहा कि आतंकवाद शांति के लिए बड़ा खतरा है और इसे किसी भी हाल में राज्य की नीति का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। दुनिया के सभी देशों को आतंकवाद के हर रूप के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना होगा।

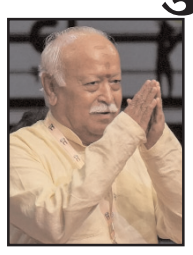
युद्ध नहीं बातचीत से निकलेगा शांति का रास्ता

आतंकवाद पर दुनिया को एकजुट होने की जरूरत

जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता। इसके पीछे कोई तर्क या बहाना स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके बावजूद आतंकवादी गतिविधियां जारी हैं, क्योंकि कुछ देश इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाने के बजाय अपने राजनीतिक हितों को ज्यादा महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास में आतंकवाद के खतरों से जुड़े कई सबक मिल चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ देश अपने फायदे के हिसाब से फैसले लेते हैं। विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि अब समय आ गया है कि दुनिया आतंकवाद के खिलाफ ज्यादा मजबूत इच्छाशक्ति दिखाए। सभी देशों को मिलकर इसके हर रूप और तरीके का मुकाबला करना चाहिए। आतंकवाद के प्रति किसी भी तरह की नरमी वैश्विक शांति के प्रयासों को कमजोर करती है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने दिया संदेश

स्वयंसेवकों का व्यवहार समाज के लिए बने अनुकरणीय



जबलपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा है कि संघ की वास्तविक पहचान उसके स्वयंसेवकों के आचरण से ही होती है। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवक का आचरण और व्यवहार ऐसा होना चाहिए, जो समाज के लिए पूरी तरह से अनुकरणीय बने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. भागवत शनिवार को जबलपुर के नरसिंह मंदिर स्थित सरस्वती शिक्षा परिषद एवं विद्या भारती कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता मिलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। लगभग एक घंटे तक चले इस कार्यक्रम में उन्होंने मुख्य शिक्षक और उससे ऊपर के दायित्वों पर कार्यरत स्वयंसेवकों को संबोधित किया तथा मार्गदर्शन दिया।

स्वयंसेवक ही संगठन का वास्तविक प्रतिनिधि

कार्यक्रम के दौरान डॉ. मोहन भागवत ने स्पष्ट रूप से कहा कि संघ न तो किसी कार्यालय से बनता है, न ही किसी शाखा या किसी समूह से। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवक ही संघ का असली प्रतिनिधि होता है। स्वयंसेवक का व्यवहार और उसका आचरण ही समाज को संघ के बारे में सही संदेश और जानकारी देता है। सरसंघचालक ने कहा कि संघ में आने का भाव कभी भी कुछ पाने का नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज को देने का होना चाहिए।

निस्वार्थ सेवा और समर्पण की भावना

डॉ. भागवत ने कहा कि स्वार्थ के लिए संघ में आने वाला व्यक्ति स्वयंसेवक के वास्तविक भाव को कभी नहीं समझ सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि यहां कुछ हासिल करने की अपेक्षा से नहीं, उन्होंने कहा कि एक स्वयंसेवक के लिए समर्पण और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव ही सबसे महत्वपूर्ण होता है।

ओडिशा को बड़ी सौगात-पीएम मोदी ने आरबीआई के डेटा सेंटर का किया उद्घाटन, बोले-

हमारी प्राथमिकता विकास है

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया। करीब 169 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस सुविधा को देश की डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता विकास है और विकास का लाभ गांवों, छोटे शहरों तथा समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए।



वाराणसी में पीएम ने 7 किमी रोड शो भी किया

टेक्सटाइल यूनिट के उद्घाटन के बाद मोदी ने दोपहर करीब 12 बजे पुलिस लाइन से नमो घाट तक करीब 7 किलोमीटर का रोड शो किया। कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने गुलाब की पंखुड़ियां बरसाईं। मोदी ने कार से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निवासियों का अभिवादन करते हुए पुलिस लाइन की ओर रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने लोगों की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया।

आरबीआई के नए डेटा सेंटर से देश को क्या फायदा होगा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भुवनेश्वर में डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन ओडिशा और पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित, सक्रिय प्रशासन और सुशासन के मॉडल पर काम कर रही है। आरबीआई का यह नया केंद्र डिजिटल वित्तीय सेवाओं को अधिक सुरक्षित, भरोसेमंद और प्रभावी बनाने में मदद करेगा। इससे देश की महत्वपूर्ण बैंकिंग और भुगतान प्रणालियों को संचालित करने के लिए सुरक्षित तकनीकी आधार मिलेगा।

डिजिटल बैंकिंग और आम लोगों को कैसे मिल रहा है फायदा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग ने देश के लोगों को चौबीसों घंटे बैंकिंग सेवाओं से जोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि अब ऐसे लोग भी बैंक से सस्ता और आसान कर्ज ले सकते हैं, जिनके पास गारंटी देने के लिए संपत्ति नहीं है। छोटे कारोबारी, पारंपरिक कारीगर, रेहड़ी-पटरी वाले और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2014 में हर परिवार को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। इन खातों में सालाना शुल्क और न्यूनतम बैलेंस रखने की शर्त नहीं है। इनसे सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने में मदद मिली है।

भारत के दुश्मनों को वायुसेना प्रमुख की चेतावनी, कहा-

कोई लक्ष्य हमारी पहुंच से बाहर नहीं



नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पश्चिमी मोर्चे पर 1200 किलोमीटर की चौड़ाई और 200 किलोमीटर की गहराई तक सटीक हमले किए। इससे साबित हुआ कि वायुसेना की पहुंच से बाहर कोई लक्ष्य नहीं है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने रविवार को यह बात कही। उनका यह बयान पाकिस्तान के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने वायुसेना की क्षमता आधारित रणनीति को सही साबित किया। हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि इस अभियान में मिली सफलता के आधार पर वायुसेना को अपनी तैयारियों में ठहराव नहीं आने देना चाहिए। भविष्य में इस क्षमता को और व्यापक तथा मजबूत बनाने पर ध्यान देना होगा।

वायु शक्ति का बेहतर इस्तेमाल जरूरी

थिएटराइजेशन पर चर्चा करते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि असली सवाल यह है कि एकीकृत सैन्य ढांचे के भीतर वायु शक्ति का अधिकतम प्रभावी इस्तेमाल कैसे किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत यह होना चाहिए कि जहां जरूरी हो, वहां नियंत्रण केंद्रीय स्तर पर रखा जाए और जहां उपयुक्त हो, वहां कार्रवाई करने की जिम्मेदारी विकेंद्रीकृत हो।

थिएटराइजेशन पर क्या बोले वायुसेना प्रमुख? भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने कहा कि थिएटराइजेशन की प्रक्रिया का उद्देश्य लड़ाकू विमानों को भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर स्थायी रूप से बांटना नहीं है। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि भारतीय वायुसेना तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त संचालन और एकीकरण की प्रक्रिया के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

एसआईआर सॉफ्टवेयर की जानकारी देने से चुनाव आयोग का इनकार, कहा- यह ट्रेड सीक्रेट

नई दिल्ली, एजेंसी

चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां पहचानने के लिए इस्तेमाल किए गए सॉफ्टवेयर की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग ने आरटीआई के जवाब में कहा- यह जानकारी ट्रेड सीक्रेट और इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़ी है। इसे सूचना का अधिकार कानून के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। आयोग ने यह भी साफ नहीं किया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां पहचानने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया गया था या नहीं। दो दिन पहले सूचना का अधिकार एक्टिविस्ट लोकेश के. बत्रा को सूचना का अधिकार के तहत मिले जवाब से पता चला कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 29 जुलाई को कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन को अलग-अलग पत्र लिखे थे। इनमें उन्होंने डिप्टी इलेक्शन कमीश्नर मनीष गर्ग के कामकाज पर सवाल उठाए थे। दोनों आयुक्तों ने अधिकारियों के बीच काम बांटने के एक आदेश पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि यह आदेश चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना जारी किया गया। सूचना का अधिकार से मिले दस्तावेजों के मुताबिक, कैबिनेट सचिवालय ने कहा कि ये पत्र पूरे चुनाव आयोग की ओर से भेजी गई आधिकारिक शिकायतें नहीं थीं।



ऑपरेशन ट्राइडेंट...

अंतरराष्ट्रीय नार्को-कार्टेल ध्वस्त, 38 जगहों पर एक साथ छापेमारी, 18 गिरफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी

गृह मंत्री अमित शाह ने नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान को लेकर केंद्र की सख्त कार्रवाई की बात कहते हुए उपलब्धियां गिनाई हैं। अमित शाह ने एक्स पर कहा- मोदी सरकार ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए नशीले पदार्थों के खिलाफ एक और जोरदार प्रहार किया है। 23 अक्टूबर को हमारी एजेंसियों ने असम, मिजोरम और मणिपुर में 38 जगहों पर एक साथ छापेमारी की और एक अंतरराष्ट्रीय नार्को-कार्टेल (नशीले पदार्थों के तस्कर गिरोह) को ध्वस्त कर दिया। इस ऑपरेशन में 100 करोड़ रुपये के हवाला लेनदेन का पता चला, 1,424 बैंक खाते फ्रीज किए गए, 17.82 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई, 500 डेटोनेटर और 12 लाख रुपये नकद बरामद हुए, और 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया।



क्या है ऑपरेशन ट्राइडेंट

इस ऑपरेशन के जरिए सुरक्षा एजेंसियों ने पूर्वोत्तर (असम, मणिपुर, मिजोरम) के रास्ते चल रहे एक संगठित ड्रग तस्कर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान अब तक 18 प्रमुख संदिग्धों/तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस ऑपरेशन में न केवल नशीले पदार्थों की जब्ती हुई, बल्कि ड्रग्स के पैसों को ठिकाने लगाने वाले 100 करोड़ रुपये से अधिक के हवाला लेनदेन का भी भंडाफोड़ हुआ है।

'डेथ ट्रायंगल कॉरिडोर' के जरिए तस्करी

यह नेटवर्क 'डेथ ट्रायंगल कॉरिडोर' के जरिए भारत, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं से नशीले पदार्थों की तस्करी करता था। यह कार्रवाई 31 दिसंबर 2029 तक नशीले पदार्थों के हर नेटवर्क को खत्म करने के भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। भारत तब तक प्रहार करता रहेगा, जब तक कि नार्को-कार्टेल का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता। केंद्रीय एजेंसियों और तीनों राज्यों की पुलिस बलों से बनी नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाने वाली टीम को हार्दिक बधाई।

टेंपल | 1 नवंबर से शुरू होंगे प्री-ऑर्डर, कीमत में लाइफटाइम सब्सक्रिप्शन भी शामिल

85 हजार में मिलेगा ब्रेन मॉनिटरिंग गैजेट

नई दिल्ली (एजेंसी)

जोमैटो के सह-संस्थापक दीपिंदर गोयल के ब्रेन मॉनिटरिंग गैजेट टेंपल की कीमत का खुलासा हो गया है। इस डिवाइस की कीमत 85,000 रुपये रखी गई है। कंपनी के शुरुआती बैच के लिए प्री-ऑर्डर 1 नवंबर 2026 से शुरू होंगे। कीमत में लाइफटाइम सब्सक्रिप्शन भी शामिल है।

टेंपल की कीमत की जानकारी कंपनी की ओर से कुछ यूजर्स को भेजे गए अर्ली-बर्ड इनवाइट के जरिए सामने आई है। इनवाइट के मुताबिक, यूजर्स टेंपल ऐप के माध्यम से आम प्री-ऑर्डर शुरू होने से पहले डिवाइस बुक कर सकेंगे। शुरुआती बैच में डिवाइस सीमित संख्या में उपलब्ध होंगे।



ब्रेन के ब्लड फ्लो को करता है ट्रैक

टेंपल को माथे के पास चिपकाया जाता है। यह डिवाइस ब्रेन में रक्त प्रवाह की निगरानी करता है। गोयल ने इस तकनीक को ब्रेन फ्लो नाम दिया है। इसका काम स्मार्टवॉच और सामान्य फिटनेस ट्रैकर से अलग है, क्योंकि यह ब्रेन के ब्लड फ्लो को ट्रैक करने पर केंद्रित है।

छह रंगों में होगा उपलब्ध

दीपिंदर गोयल कई बार टेंपल पहने नजर आ चुके हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु भी लाइव मैच के दौरान इसे पहन चुकी हैं। गोयल के मुताबिक, यह गैजेट छह रंगों में उपलब्ध होगा। इनमें ट्रू गोल्ड, रोज गोल्ड और ब्लैक मिरर जैसे विकल्प शामिल हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरवर का जिला स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

उज्जैन। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, शासकीय स्वास्थ्य योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विक्रम रघुवंशी के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जितेंद्र सिंह राजपूत, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. रविंद्र कुमार पाल द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरवर, ब्लॉक ताजपुर का संयुक्त भ्रमण किया गया।

निरिक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य केंद्र में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण में पाया गया कि अस्पताल में ॥स्ह्वह्लस् पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ओपीडी पर्ची बनाई जा रही थी। इसके साथ ही ई-क्क्रस्रू (प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान) के अंतर्गत हाई रिस्क प्रेग्नेंसी (॥ञ्क्क) वाली गर्भवती महिलाओं की जांच एवं उपचार महिला चिकित्सक द्वारा किया जा रहा था।अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य केंद्र के डिलीवरी रूम, प्रसवोत्तर देखभाल वार्ड



(क्कह्ष्ट वार्ड), प्रयोगशाला (लेबोरेट्री) एवं कोल्ड चेन रूम का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया। इस दौरान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, गर्भवती महिलाओं की समुचित देखभाल, प्रसव के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं, जांच सुविधाओं तथा टीकों के सुरक्षित रखरखाव से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।

संयुक्त भ्रमण के दौरान संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले सभी मरीजों को समय पर बेहतर उपचार एवं आवश्यक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। गर्भवती महिलाओं, विशेषकर हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं की नियमित निगरानी एवं समुचित उपचार सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्रसव कक्ष एवं पीएनसी वार्ड में स्वच्छता बनाए रखने, आवश्यक उपकरणों एवं संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा शासन द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए।

अधिकारियों ने टीकों के सुरक्षित भंडारण हेतु कोल्ड चेन व्यवस्था को निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाए रखने तथा स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित ऑनलाइन पोर्टल पर सभी आवश्यक जानकारियों की समय पर एवं शत-प्रतिशत प्रविष्टि सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

इस अवसर पर जिला कम्युनिटी मोबाईलजर श्री अनस कुरैशी सहित अन्य स्टॉफ उपस्थित थे।

निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया निर्धारित समय-सारणी के अनुसार होगी



उज्जैन । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की गई है। कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक जानकारी एवं प्रक्रिया से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराने के लिए शनिवार, 24 अक्टूबर को प्रशासनिक संकुल भवन के द्वितीय तल पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक में संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संदीप सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय-सारणी की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया निर्धारित समय-सारणी के अनुसार संपादित की जाएगी। उन्होंने बताया कि 2 नवम्बर 2026 तक मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण एवं पुनर्व्यवस्थापन किया जाएगा। इसके पश्चात 12 नवम्बर 2026 को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 12 नवम्बर से 11 दिसम्बर 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि निर्धारित की गई है। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का 28 दिसम्बर 2026 तक निराकरण किया जाएगा। संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

निर्माण कार्यों में तेजी लाएं, – संभागायुक्त श्री सिह



उज्जैन । सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के अंतर्गत शहर में चल रहे विकास एवं निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा एवं स्थल निरीक्षण किया जा रहा है। शनिवार को संभागायुक्त सह सिंहस्थ मेला अधिकारी श्री आशीष सिंह एवं कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने नगर निगम द्वारा कराए जा रहे एमआर-4 एवं एसआर-1 सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान संभागायुक्त श्री आशीष सिंह ने मौके पर उपस्थित नगर निगम के इंजीनियरों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिंहस्थ-2028 के लिए निर्माण कार्यों को जल्द पूर्ण करे। इसलिए सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए तथा किसी भी कारण से कोई भी कार्य प्रभावित नही होना चाहिए। उन्होंने निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में पर्याप्त संख्या में टीमें लगाकर कार्य की गति बढ़ाई जाए, ताकि निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण हो सके।

संभागायुक्त श्री आशीष सिंह एवं कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने सबसे पहले ढांचा भवन से एमआर-5 तक किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कार्य के दौरान आमजन को वैकल्पिक मार्ग की जानकारी देने वाले स्पष्ट एवं पर्याप्त संख्या में साइनेज लगाए जाएं, ताकि निर्माण कार्य के दौरान नागरिकों को आवागमन में असुविधा न हो। इसके पश्चात नगर निगम द्वारा निर्माणाधीन 30 मीटर चौड़े एसआर-1 सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मौके पर निर्माण कार्य की प्रगति, अब तक पूर्ण किए गए कार्य तथा आगामी कार्य योजना और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जानकारी ली। संभागायुक्त श्री सिंह ने निर्देश दिए कि एसआर-1 सड़क निर्माण कार्य में अलग-अलग टीमें लगाकर कार्य को गति दी जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। निर्माण कार्य में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नही होना चाहिए। उन्होंने संबंधित निर्माण विभाग के इंजीनियरों को निर्देशित किया कि वे अनिवार्य रूप से कार्यस्थल पर उपस्थित रहें और निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति पर सीधी नजर रखे जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। निरीक्षण के दौरान अपर मेला अधिकारी श्री ओमप्रकाश सनोडिया, एसडीएम श्री एलएन गर्ग सहित नगर निगम के अधिकारी एवं इंजीनियर तथा संबंधित निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

000

सीएमएचओ डॉ. विक्रम रघुवंशी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इंगोरिया एवं उप स्वास्थ्य केंद्र खरसोदखुर्द का किया औचक निरीक्षण

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं का समय पर प्रबंधन एवं पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ देने के निर्देश

उज्जैन । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विक्रम रघुवंशी, जिला उज्जैन द्वारा जिले में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने, शासन की जनकल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को समय पर उपलब्ध कराने तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों के निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इंगोरिया एवं उप स्वास्थ्य केंद्र खरसोदखुर्द का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।

निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ डॉ. रघुवंशी ने स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध सेवाओं, मरीजों को दी जा रही सुविधाओं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों, अभिलेखों के संधारण तथा शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता बनाए रखने तथा प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

एनआरसी में निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार बेड ऑक्यूपेंसी सुनिश्चित करें

सीएमएचओ ने पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में बेड ऑक्यूपेंसी निर्धारित प्रोटोकॉल एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने तथा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कार्य करने पर जोर दिया।



प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की जांच एवं उपचार समय पर करें

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविर में गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली गई। सीएमएचओ ने निर्देश दिए कि शिविर में आने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला की आवश्यक जांच, स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार समय पर सुनिश्चित किया जाए। गर्भवती महिलाओं की निर्धारित 04 प्रसवपूर्व जांच समय पर पूर्ण कराई जाएं तथा उनकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार आवश्यक परामर्श एवं उपचार उपलब्ध कराया जाए।

उन्होंने विशेष रूप से हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनका नियमित फॉलोअप करने तथा संभावित जटिलताओं वाली गर्भवती महिलाओं को समय रहते बर्थ वेटिंग में भर्ती कराने के निर्देश दिए, ताकि सुरक्षित संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किया जा सके और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके।

हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं की सूची चस्पा कर समय पर करें प्रबंधन

सीएमएचओ ने निर्देश दिए कि जिले की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं की अद्यतन सूची चस्पा की जाए। संबंधित स्वास्थ्यकर्मी ऐसी महिलाओं की नियमित निगरानी करें तथा उनकी स्थिति के अनुसार समय पर उपचार एवं रेफरल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मॉडरेट एनीमिया, गंभीर एनीमिया एवं पीआईएच (गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप) से संबंधित मामलों का निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार समय पर प्रबंधन किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाए।

आयुष्मान कार्ड एवं सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करें

डॉ. रघुवंशी ने पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी प्रकरणों का समय-सीमा में संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

नवजात शिशुओं की गृह आधारित देखभाल एवं फॉलोअप पर जोर

, आशा कार्यकर्ताओं द्वारा नवजात शिशुओं की गृह आधारित देखभाल एवं नियमित फॉलोअप सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी, आवश्यक परामर्श तथा किसी भी खतरे के लक्षण दिखाई देने पर समय पर उपचार की व्यवस्था की जाए, जिससे शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं समय-सीमा में पूर्ण करें द्यसामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इंगोरिया में निर्माणाधीन बाउंड्रीवॉल का अवलोकन करते हुए सीएमएचओ ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वच्छता बनाए रखने तथा मरीजों को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। पैथोलॉजी जांच गुणवत्ता पूर्ण समय पर किए जाने के निर्देश द्य

ऑनलाइन ओपीडी, रिकॉर्ड संधारण एवं दवा वितरण व्यवस्था दुरुस्त रखें

सीएमएचओ ने निर्देश दिए कि ओपीडी पर्चियां ऑनलाइन बनाई जाएं तथा सभी आवश्यक रिकॉर्ड एवं अभिलेख नियमित रूप से अद्यतन रखे जाएं। दवाइयों का वितरण निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाए तथा दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन इंडेंट समय पर किया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य संस्थाओं में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था रखने और मरीजों के साथ मधुर एवं संवेदनशील व्यवहार करने के निर्देश भी दिए।

अधिकारी–कर्मचारी मुख्यालय पर रहकर सेवाएं दें

डॉ. रघुवंशी ने सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे अपने निर्धारित मुख्यालय पर निवास करते हुए समय पर उपस्थित रहें तथा आमजन को नियमित एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की किए जाने निर्देश द्य

निरीक्षण के दौरान ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. विजेंद्र सिंह अजनार, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री किरण मंडलोई सहित संबंधित स्वास्थ्य संस्थाओं के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

00

ब्रह्मज्ञान जागृति का अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि इसकी शुरुआत, सेवा दिखावे के लिए नहीं सच्चे भाव से हो

79वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने दिया प्रेम, भक्ति और एकत्व का संदेश



उज्जैन। हरियाणा के समालखा स्थित निरंकारी आध्यात्मिक स्थल पर आयोजित चार दिवसीय 79वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के पहले दिन निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने देश-विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने प्रेम, भक्ति और मानवीय एकत्व की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि ब्रह्मज्ञान जागृति का अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत है। सच्ची जागृति वही है, जब मनुष्य हर पल निराकार के एहसास के साथ प्रेम, विश्वास और विनम्रता से जीवन व्यतीत करे।

सतगुरु माता जी ने अपने प्रवचन में कहा कि सत्संग में केवल उपस्थित होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वहां से मिली शिक्षाओं को अपने व्यवहार में अपनाना आवश्यक है। हमारी सेवा और समर्पण दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे भावों से युक्त होना चाहिए। दूसरों के प्रति प्रेम रखना, निंदा और अहंकार से बचना तथा अपनी वाणी और कर्मों से अच्छाई दर्शाना ही वास्तविक आध्यात्मिक जागृति की पहचान है। उन्होंने श्रद्धालुओं को प्रेरित किया कि परमात्मा के दिए साधनों का उपयोग मानवता की सेवा और परोपकार में करें। जीवन की हर परिस्थिति में मन की शांति, सहजता और विश्वास बनाए रखें।

सेवादल रैली के साथ दूसरे दिन का शुभारंभ- समागम के दूसरे दिन की शुरुआत भव्य सेवादल रैली से हुई। इसमें देश-विदेश से आए हजारों सेवादल सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शारीरिक व्यायाम, खेलकूद, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और लघु नाटिकाओं के माध्यम से अनुशासन, सहयोग और निःस्वार्थ सेवा का संदेश दिया गया। इससे पूर्व सतगुरु माता जी ने शांति और एकत्व के प्रतीक श्वेत ध्वज का ध्वजारोहण किया।

रैली को संबोधित करते हुए माता जी ने कहा कि सेवा केवल ड्यूटी निभाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन का अभिन्न अंग है। सच्चा सेवादार वही है जो निरंकार को हृदय में बसाकर हर परिस्थिति में मानवता के कल्याण के लिए तत्पर रहे। निरंकार पर अटूट विश्वास रखते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और तन, मन, धन को परोपकार में लगाकर जीवन सार्थक बनाएं।

रैली के दौरान संत निरंकारी सेवादल के मुख्य संचालक एस के जुनेजा ने विश्वभर से आए सेवादल स्वयंसेवकों की ओर से सतगुरु माता जी के चरणों में श्रद्धा अर्पित की।

युवा मंच संसार समिति आज लगाएगी विशाल नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर, मोतियाबिंद के होंगे ऑपरेशन

उज्जैन। युवा मंच संसार समिति और लायंस क्लब उज्जैन महाकाल के संयुक्त तत्वावधान में आज रविवार 25 अक्टूबर को विशाल नि:शुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इंदिरा नगर में छोटे तालाब के पास स्थित आनंदेश्वर महादेव मंदिर परिसर में यह शिविर सुबह 10.30 से दोपहर 1 बजे तक लगेगा। आयोजन में युवा मंच की विभिन्न इकाइयों की विशेष भागीदारी रहेगी।

शिविर संयोजक गोपाल बागरवाल और अध्यक्ष मनोहर परमार के अनुसार शिविर में आंखों की जांच कर आवश्यकतानुसार मुफ्त दवाइयां दी जाएंगी। मोतियाबिंद के चयनित रोगियों के ऑपरेशन अमृत हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इंगोरिया के सहयोग से



निःशुल्क किए जाएंगे। ऑपरेशन के लिए मरीजों को आधार कार्ड की फोटोकॉपी लाना अनिवार्य है। मुख एवं दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. मनु सागर मारोठिया द्वारा दांतों का परीक्षण किया जाएगा। लोटस हॉस्पिटल उज्जैन के सहयोग से ब्लड प्रेशर, शुगर की मुफ्त जांच और होम्योपैथिक दवाइयों का वितरण होगा।

शिविर में डॉ. एम के पटेल, डॉ. प्रवीण पण्ड्या, डॉ. अमित पटेल, डॉ. खुशबु अंसारी और डॉ. संजय जोशी सेवाएं देंगे। एक्यूप्रेशर सुजोग चिकित्सा में अनिरुद्ध नाहर, करण पण्ड्या और लक्ष्मण सिंह मरीजों का उपचार करेंगे।

आयोजक संस्था इंदिरा नगर विकास एवं सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष धनीराम सयकवार, उपाध्यक्ष अमित विश्वकर्मा, संयोजक पार्षद दिलीप सिंह परमार सहित डॉ. जितेन्द्र जैववानी, हेमन्त पांचाल, योगेन्द्र शुक्ला, नितिन शर्मा और दिलीप राठौर आयोजन में जुटे हैं।

युवा मंच संसार समिति के महेश सोनोने, फूलचंद जरिया, उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रीवास्तव, सचिव विजय तिवारी, सहसचिव पारस जैन, कोषाध्यक्ष ओम हरोड, धर्मेन्द्र जैन, कार्य प्रभारी किशन भाटी, संयोजक विट्ठल नागर सेवाएं देंगे। महिला युवा मंच संसार समिति से संयोजक गीता राठी, अध्यक्ष लक्ष्मी लश्करी, उपाध्यक्ष आरती गुप्ता व नीता अतिया, सचिव नीता राठौर, कोषाध्यक्ष योगिता आर्य, महामंत्री संतोष भारद्वाज, पिंकी यादव, कविता रॉय व्यवस्था संभालेंगी।

युवा मानव सेवा समिति के संयोजक रितेश वर्मा, अध्यक्ष डॉ. सागर मारोठिया, उपाध्यक्ष अर्जुन माली व अनिल पांचाल, सचिव लोकेन्द्र राठी, सहसचिव अनिल लश्करी, कोषाध्यक्ष नरेन्द्र डोरिया, संगठन मंत्री अनिल दुबे व दिनेश परमार मौजूद रहेंगे। आयोजन में लायंस क्लब के ला. नरेन्द्र राठी, ला. आरएस मिल, ला. अजीत बैराठी, ला. चन्द्र गुप्ता, ला. प्रदीप सिंह, ला. आरपी सिंह, ला. गुरुदीप सैनी, ला. पंकज नीमा, ला. शैलेष शर्मा, ला. सुधीर गुप्ता, ला. पवन त्रिपाठी, ला. विजय तिवारी सहयोग करेंगे।

साथ ही गेहूं दान वितरण समिति के राजेश राणा, शिवनारायण जागीरदार, वीरेन्द्र परमार, अशोक शर्मा तथा अनुदान समिति के महेश गुप्ता, संतोष शर्मा और बाबूलाल मारोठिया भी अपनी सेवाएं देंगे।

सिंहस्थ-2028 7 किसानों की सहभागिता से विकसित होगी टेंट सिटी

उज्जैन। संभागायुक्त श्री आशीष सिंह एवं कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह की उपस्थिति में टेंट सिटी विकसित करने के संबंध में किसानों एवं प्रशासन की बैठक आयोजित हुई।

बैठक में पर्यटन विभाग के सहयोग से टेंट सिटी के विकास, संचालन एवं आवश्यक सुविधाओं पर चर्चा हुई। किसानों ने पहल में रुचि दिखाते हुए अपने सुझाव साझा किए।

इस पहल से श्रद्धालुओं को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी तथा स्थानीय किसानों को आर्थिक एवं रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

सदावल हेलीपैड के सभी काम दिसंबर माह के अंत तक पूरे करने के निर्देश



उज्जैन । संभाग आयुक्त एवं मेला अधिकारी श्री आशीष सिंह ने आज सिंहस्थ 2028 के लिए लोक निर्माण विभाग,नगर निगम,एम पी आर डी सी एवं सेतु निगम के द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा में उन्होंने सदावल हेलीपैड के लैंडस्कैपिंग,फ्लोरिंग और फर्निशिंग के काम में देरी होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए हैं कि यह काम किसी भी स्थिति में दिसंबर माह के अंत तक पूर्ण हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की टाइमलाइन बार-बार नहीं बढ़ाई जाएगी। जो टाइमलाइन निश्चित है उसी समय सीमा में सभी इंजीनियरों को काम पूरा करना है।

??संभाग आयुक्त ने कहा है कि यदि निर्धारित समय सीमा में कार्य नहीं होता है तो संबंधित उपयंत्री को निलंबित किया जाएगा। इसी के साथ सभी इंजीनियर्स को निर्देशित किया गया है कि निर्माण कार्य समय सीमा में तेजी से करने के लिए अलग-अलग टीम को इंगेज किया जाए जिससे कि काम समय से पूरा हो सके। ??बैठक में कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह,स्मार्ट सिटी की सीईओ श्रीमती नेहा जैन, अपर आयुक्त नगर निगम श्री संतोष टैगोर, अपर मेला अधिकारी ओमप्रकाश सनोड़िया, उप मेला अधिकारी श्री संदीप सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

मार्च से जून 2027 के बीच कई पुलों का काम होगा पूरा

बैठक में संभाग आयुक्त ने शिप्रा नदी पर सेतु निगम द्वारा बनाये जा रहे ब्रिजों एवं रेलवे ओवर ब्रिज कार्यों की समीक्षा की।

शहडोल जिले में रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज 461.73 करोड़ रुपये के 134 विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन

45 विकास कार्यों का लोकार्पण और 89 निर्माण कार्यों का किया भूमिपूजन

सड़क, पुल, विद्यालय भवन, छात्रावास, पुलिस भवन, पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युत एवं खेल सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल

शहडोल। (अविरल गौतम) मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज जिले में आयोजित तेंदूपत्ता संग्राहकों के बोनस वितरण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अंतर्गत 461 करोड़ 73 लाख रुपये की लागत के 134 निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इनमें 82 करोड़ 28 लाख रुपये की लागत के 45 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 379 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत के 89 निर्माण कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।इन विकास कार्यों में सड़क एवं पुल निर्माण, शासकीय विद्यालयों के भवन, छात्रावास, महाविद्यालयीन भवन, पुलिस कार्यालय एवं आवास, विद्युत उपकेंद्र, खेल सुविधाएं, पेयजल व्यवस्था तथा ग्रामीण अधोसंरचना से संबंधित कार्य शामिल हैं। इन कार्यों के पूर्ण होने से जिले में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन, पेयजल और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सुविधाएं मजबूत होंगी।

45 विकास कार्यों का किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आठ विभागों के अंतर्गत 82 करोड़ 28 लाख रुपये की स्वीकृत राशि के 45 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा वन विभाग के कार्य शामिल हैं। मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम के एक कार्य के लिए 22.86 करोड़ रुपये तथा मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं



अधोसंरचना विकास मंडल के एक कार्य के लिए 22.14 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं। लोक निर्माण विभाग के दो कार्यों के लिए 14.92 करोड़ रुपये, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 14 कार्यों के लिए 8.76 करोड़ रुपये तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 21 कार्यों के लिए 5.21 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दो कार्यों के लिए 4.43 करोड़ रुपये, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के दो कार्यों के लिए 3.60 करोड़ रुपये तथा वन विभाग के दो कार्यों के लिए 36 लाख रुपये की स्वीकृत राशि निर्धारित है। इन कार्यों से सड़क संपर्क, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।

89 निर्माण कार्यों का किया भूमिपूजन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिले में 379 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत के 89 निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। इन कार्यों में सड़क एवं पुल निर्माण, शासकीय विद्यालयों के भवन, छात्रावास, महाविद्यालयीन भवन, पुलिस विभाग के कार्यालय एवं आवास, विद्युत उपकेंद्र तथा खेल सुविधाओं के विकास से संबंधित कार्य शामिल हैं।

लोक निर्माण विभाग के 36 निर्माण कार्य

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 36 निर्माण कार्य शामिल हैं। इनमें विभिन्न गांवों को जोड़ने वाले पहुंच मार्गों का निर्माण, सड़कों का मजबूतीकरण तथा नदियों पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण के कार्य सम्मिलित हैं। प्रमुख कार्यों में साखी पुरनिहा टोला मार्ग, साखी से छत्तीसगढ़ पहुंच मार्ग, भानपुर-खटोलिया-हर्दी-समातपुर मार्ग, बिरौंड़ी से महुआ मार्ग, जैतपुर तहसील पहुंच मार्ग तथा अन्य ग्रामीण सड़कों का निर्माण शामिल है। इसके अतिरिक्त टेंघा-छीनमार मार्ग में गौरीहारी नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग तथा नरवार-गोड़ारू मार्ग में सोन नदी के चकराघाट पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण भी शामिल है। इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और सड़क संपर्क बेहतर बनेगा।

जनजातीय कार्य विभाग के 38 निर्माण कार्य

जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 38 निर्माण कार्य शामिल हैं। इनमें सोहागपुर, जयसिंहनगर, गोहपारू और बुढ़ार विकासखंड के विभिन्न शासकीय हाई स्कूलों के भवन निर्माण के साथ छात्रावास एवं आश्रमशाला भवनों का निर्माण शामिल है। इन कार्यों से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक एवं आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

शिक्षा एवं उच्च शिक्षा अधोसंरचना का विस्तार

मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के अंतर्गत कन्या शिक्षा परिसर गोहपारू का निर्माण तथा शासकीय पीजी कॉलेज बुढ़ार में नवीनीकरण, उन्नयन एवं नवीन निर्माण कार्य शामिल हैं। इन कार्यों से शैक्षणिक संस्थानों की सुविधाओं का विस्तार होगा और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

पुलिस भवन एवं आवास संबंधी कार्य

मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक कार्यालय शहडोल, बुढ़ार क्षेत्र के थाना भवनों, ब्यौहारी थाना परिसर में आरक्षक आवासगृह तथा अन्य पुलिस भवनों से संबंधित निर्माण कार्य शामिल हैं। इनसे पुलिस विभाग की अधोसंरचना और आवासीय सुविधाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।

सड़क, पेयजल एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क से संबंधित कार्य शामिल हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों से पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिलेगी, जबकि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के निर्माण कार्य स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अधोसंरचना के विकास में योगदान देंगे।

वन, ऊर्जा एवं खेल सुविधाओं को मिलेगा बढ़ावा

वन विभाग के अंतर्गत काष्ठागार कार्यालय भवन तथा वनरक्षक नाका निर्माण के कार्य शामिल हैं। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों से संबंधित कार्य किए जाएंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत विचारपुर स्थित खेलो इंडिया स्मॉल फुटबॉल सेंटर के लिए फुटबॉल मैदान, बाउंड्रीवॉल, चेंजिंग रूम, ऑफिशियल रूम एवं पवेलियन का निर्माण शामिल है। इससे क्षेत्र में खेल गतिविधियों और खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा।

अन्य विभागों के निर्माण कार्य

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अंतर्गत बुढ़ार-अमरकंटक मार्ग पर कोयला खनन के लिए डायवर्सन मार्ग निर्माण का कार्य शामिल है। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत सोहागपुर में 50 सीटर वरिष्ठ कन्या छात्रावास तथा वारगांव में 50 सीटर वरिष्ठ बालक छात्रावास भवन का निर्माण किया जाएगा। राजस्व विभाग के अंतर्गत तहसील परिसर में एसडीएम कार्यालय भवन निर्माण का कार्य भी शामिल है।

जिले की आधारभूत सुविधाओं को मिलेगी मजबूती

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 134 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किए जाने से शहडोल जिले में सड़क संपर्क, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं, पुलिस अधोसंरचना, विद्युत व्यवस्था, छात्रावासों तथा खेल सुविधाओं के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा।

विभिन्न विभागों के माध्यम से इन कार्यों के क्रियान्वयन से जिले की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

अवैध पैकारी पर जिम्मेदार मौन, पाली क्षेत्र में गली-गली बिक रही शराब

शहडोल। (दीपक द्विवेदी) संभाग के उमरिया जिले के पाली क्षेत्र में शराब की अवैध बिक्री ने विकराल रूप ले लिया है, लेकिन प्रशासन और आबकारी विभाग की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। गली-गली शराब बेचे जाने का सिलसिला इस कदर तेज़ है कि अब यह व्यापार खुलेआम हो रहा है। ठेका शराब दुकानों से शराब एमआरपी से अधिक मूल्य पर खुलेआम बेची जा रही है, और प्रशासन केवल मूकदर्शक बना बैठा है।



पाली क्षेत्र की जनता लंबे समय से इस अवैध कारोबार के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। हैरानी की बात यह है कि सरकारी ठेकों से शराब एमआरपी से अधिक कीमत पर बेची जा रही है, जो साफ तौर पर कानून का उल्लंघन है। उपभोक्ताओं से प्रति बोतल 20 से 50 रुपये तक अधिक वसूले जा रहे हैं, और जब लोग विरोध करते हैं, तो उन्हें धमकाया जाता है।

आबकारी विभाग की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध दिखाई देती है। विभाग की आंखों पर मानो पट्टी बंधी हो,न तो उन्हें अवैध बिक्री दिखाई दे रही है और न ही एमआरपी से अधिक वसूली की शिकायतें सुनाई दे रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों के बीच कोई न कोई मिलीभगत ज़रूर है, जिससे यह पूरा अवैध तंत्र फल-फूल रहा है।

यह मामला सिर्फ अवैध शराब बिक्री का नहीं, बल्कि प्रशासनिक विफलता और जिम्मेदारियों से भागते तंत्र की पोल खोलता है। अब देखना यह है कि क्या कोई ईमानदार पहल होगी, या फिर पाली की गलियों में शराब इसी तरह बहती रहेगी।

जिला मुख्यालय के शहर से बाहर हो खूनी राजमार्ग

नागरिकों की जिंदगी लील रही सड़क को बायपास करने की फिर उठी मांग

उमरिया। (अविरल गौतम) में शुक्रवार की शाम शहर के लालपुर मे हाईवे पर हुई भीषण दुर्घटना मे यश हेमनानी की मौत ने जिम्मेदारों पर फिर सवाल उठाए हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि करोड़ों रुपये खर्च कर बनाई गई नेशनल हाईवे को वापस जिला मुख्यालय मे लाने का विचार किसका था। जब सड़क को नगर मे ही उतारना था, तो बायपास का क्या औचित्य है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है और यह किसके लिए किया गया गौरतलब है कि कटनी-शहडोल राष्ट्रीय राजमार्ग 78/43 को ग्राम भरौला से बायपास किया गया है, लेकिन इसके बाद नगरीय क्षेत्र के भंगहा, छटन और घंघरी ओवरब्रिज होते हुए फिर से पुरानी सड़क यानी लालपुर मे उतार दिया गया। यहां से यह मार्ग खलेसर नाका और चपहा कॉलोनी होकर निकलता है। मतलब यह कि अरबों रुपये खर्च करने के बावजूद उमरिया के स्टेशन चौक से रामपुरी और घंघरी नाका तक करीब डेढ़ किलोमीटर के हिस्से को ही भारी वाहनों से मुक्ति मिल सकी।

भीड़ के बीच तूफानी रफ्तार



विभाग और दलालों की मिलीभगत का ही नतीजा है कि इतनी बड़ी कवायद के बावजूद यह सड़क नगर के आधा दर्जन से ज्यादा वार्डों के बीच मौजूद है, जहां दोनों ओर बड़ी आबादी निवास करती है। इन इलाकों मे दिन-रात बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं पैदल, दोपहिया वाहनों और कारों से आवागमन करते हैं। इनके बीच राखड़, कोयला इत्यादि का परिवहन करने वाले भीमकाय वाहनों की आवाजाही भी होती है। ऐसे व्यस्त मार्ग पर भी वाहन ट्रक, टैंकर और बल्कर 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं। इन्हें रोकने और नियंत्रित करने की कोशिश तो दूर, सड़क पर एक संकेतक तक नहीं लगाया गया है।

हर दुर्घटना के बाद शुरू होती कार्रवाई

गत दिवस हुई दुर्घटना और बच्चे की मौत का यह पहला वाकया नहीं है। पूर्व मे भी इसी स्थान पर दर्जनों हादसे हो चुके हैं। इनमें अधिकांश घटनाएं सड़क किनारे खड़े ट्रकों से टकराने और अनियंत्रित रफ्तार के कारण हुई हैं। ऐसे मामलों के बाद पुलिस और यातायात विभाग का अमला कार्रवाई के लिए निकल पड़ता है, लेकिन मामला पुराना होते ही हालात जस के तस हो जाते हैं। यदि गैर-जिम्मेदार चालकों के विरुद्ध नियमित और कड़ी कार्रवाई की जाती, तो दुर्घटनाओं मे कुछ कमी निश्चित तौर पर आ सकती थी।

आंदोलन और चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी

नेशनल हाईवे के निर्माण मे भी घोर अनियमितता हुई है। 14 साल से बन रही उमरिया-शहडोल सड़क अभी अधूरी है। लोगों ने बताया कि एमपीआरडीसी ने करकेली जैसी जगह पर मीडियन डिवाइडर, नाली और स्ट्रीट लाइट लगाई, लेकिन जिला मुख्यालय मे लाइट, डिवाइडर तो छोड़िए, पानी की निकासी के लिए नाली तक नहीं बनी। यह क्षेत्र की घोर उपेक्षा को दर्शाता है। नागरिकों की मांग है कि इस खूनी हाईवे को तत्काल शहर से बायपास किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो इसके विरोध मे आंदोलन, नगर बंद और चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया जाएगा।

जिले के पाली थाना क्षेत्र में एक घर मे सेंधमारी कर 12 लाख का माल ले उड़े चोर

उमरिया। (दीपक द्विवेदी) जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मझगवां मे बदमाशों द्वारा एक कच्चे मकान मे सेंधमारी कर करीब 12 लाख रुपये की संपत्ति चोरी करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार विधवा आशा कार्यकर्ता कुसुमकली यादव गत दिवस अपने कच्चे मकान मे ताला लगाकर दूसरे घर मे सोने चली गई थीं। सुबह लौटने पर दीवार मे सुरंग मिली और सामान बिखरा पड़ा था। फरियादिया के मुताबिक चोर दो पेटियों मे रखे 2 लाख 6 हजार रुपये नकद, करीब 70 ग्राम सोने और 750 ग्राम चांदी के आभूषण ले गए। इस मामले मे पाली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। क्षेत्र मे इससे पहले भी कई वारदातें हुई हैं। जिनका सुराग नहीं मिलने और ताजा घटना से पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।



उमरिया जिले के एनएच-43 पर बाबा महाकाल की निगरानी चौकी, अधिकारियों की नजरों के सामने कैसे चल रही व्यवस्था, चपहा विवाद ने खनिज विभाग को कटघरे में खड़ा किया

उमरिया। (दीपक द्विवेदी) जिले में रेत का कारोबार आखिर किसके भरोसे चल रहा है नियमों के भरोसे, जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी में या फिर ठेका कंपनी की अपनी व्यवस्था के सहारे। कोतवाली थाना क्षेत्र के चपहा में रेत परिवहन को लेकर हुए विवाद ने इन सवालों को और गंभीर बना दिया है। ह॥-43 के पास रेत ठेका कंपनी बाबा महाका' की निगरानी चौकी होने की बात सामने आई है। शिकायतकर्ता सुमित राय का आरोप है कि उन्होंने 21 अक्टूबर 2026 को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ह॥-43 से जिले के जिम्मेदार अधिकारी और खनिज विभाग के अधिकारी गुजरते हैं, तो क्या उनकी नजर इस निगरानी चौकी पर नहीं पड़ी यदि चौकी लंबे समय से संचालित थी, तो उसकी वैधानिक स्थिति की जांच पहले क्यों नहीं हुई। और यदि अधिकारियों को इसकी जानकारी थी, तो अब तक क्या कदम उठाए गए। इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है।

सड़क किनारे चौकी, फिर अधिकारियों की नजर क्यों नहीं

NH-43 जिले का प्रमुख मार्ग है। इस मार्ग से सरकारी अधिकारियों और संबंधित विभागों के वाहनों की आवाजाही होती रहती है। ऐसे में चपहा में कंपनी की निगरानी चौकी को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या अधिकारियों ने कभी यह जानने की कोशिश की कि चौकी किस अनुमति के आधार पर संचालित हो रही है।वहां तैनात कर्मचारियों की जिम्मेदारी क्या है और उन्हें कौन-कौन से अधिकार दिए गए हैं। यदि चौकी की वैधानिक स्थिति स्पष्ट नहीं थी, तो इसकी जांच समय रहते क्यों नहीं हुई।क्या संबंधित विभाग ने कभी निरीक्षण किया।इन सवालों का उत्तर जिला खनिज अधिकारी और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को देना चाहिए।

थाना प्रभारी के बयान से बढ़े सवाल

कोतवाली थाना प्रभारी मदनलाल मरावी के अनुसार, चपहा में रेत परिवहन को लेकर विवाद हुआ है और दोनों पक्षों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मामले की जांच जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी की ओर से बनाई गई निगरानी चौकी का सरकारी कागजों में पंजीयन नहीं है। यह बयान चौकी की वैधानिक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। हालांकि, पंजीयन नहीं होने की जानकारी मात्र से किसी कानूनी उल्लंघन का अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। संबंधित अनुमति, लागू नियम और चौकी के संचालन की वास्तविक स्थिति की जांच आवश्यक है। लेकिन सवाल यह जरूर है कि यदि चौकी के संचालन में किसी अनुमति या नियम का उल्लंघन हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। कंपनी की, निगरानी करने वाले विभाग की या उन अधिकारियों की जिन्होंने समय रहते इसकी जांच नहीं की।

क्या अधिकारियों की अनदेखी से बढ़ा कंपनी का हौसला



चपहा में विवाद के दौरान कुछ लोगों के हाथों में डंडे दिखाई देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि और उसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच अभी जरूरी है। किसी भी कंपनी के कर्मचारी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यदि जांच में मारपीट, धमकी या अन्य अपराध की पुष्टि होती है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में सवाल सिर्फ विवाद करने वालों तक सीमित नहीं है। यदि ह॥-43 के पास निगरानी चौकी संचालित हो रही थी, तो उसकी वैधानिक स्थिति की जांच की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की भी बनती है। क्या विभाग की निगरानी प्रभावी थी क्या कंपनी की गतिविधियों का सत्यापन किया गया। क्या अधिकारियों की कथित अनदेखी ने ऐसी व्यवस्था को बढ़ावा दिया। इन प्रश्नों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

जिला खनिज अधिकारी से जवाब मांग रहे सवाल

जिला खनिज अधिकारी को स्पष्ट करना चाहिए कि चौकी की जानकारी विभाग को थी या नहीं। यदि जानकारी थी, तो उसकी अनुमति और संचालन की जांच कब की गई।यदि जानकारी नहीं थी, तो ह॥-43 जैसे प्रमुख मार्ग के पास संचालित व्यवस्था विभाग की निगरानी से कैसे छूट गई। सुमित राय का कहना है कि शिकायत देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस को शिकायत पर की गई कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, जबकि खनिज विभाग को चौकी की वैधानिक स्थिति और अपनी निगरानी व्यवस्था पर जवाब देना चाहिए।

फिलहाल किसी अधिकारी की मिलीभगत या संरक्षण का प्रमाण सामने नहीं है। लेकिन उठे सवालों का जवाब तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर देना जरूरी है। चपहा का मामला प्रशासनिक निगरानी की परीक्षा है। जनता जानना चाहती है कि रेत का कारोबार नियमों से चलेगा या सवाल उठने के बाद भी जिम्मेदार विभाग केवल जांच का भरोसा देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेंगे।

निस्तार डिपो, बंदरों के आतंक और पेयजल समस्या को लेकर कलेक्टर को सौंपा आवेदन

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के शिविर में युवा पत्रकार रवि सेन ने उठाए नगर की मूलभूत समस्याओं से जुड़े मुद्दे

उमरिया। (अविरल गौतम) जिले के मानपुर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत 23 अक्टूबर 2026 को नगर परिषद मानपुर के मंगल भवन में आयोजित शिविर में नगर की प्रमुख मूलभूत समस्याओं को लेकर युवा पत्रकार रवि सेन ने जिला कलेक्टर उमरिया के नाम आवेदन सौंपकर शीघ्र निराकरण की मांग की। आवेदन में नगर परिषद मानपुर में निस्तार डिपो खोले जाने, लाल मुंह वाले बंदरों के आतंक से निजात दिलाने तथा वार्ड क्रमांक 5 की पेयजल व्यवस्था का पुन: भौतिक सत्यापन कर जलापूर्ति शुरू किए जाने की मांग प्रमुखता से रखी गई।

निस्तार डिपो की मांग—दाह संस्कार में भी होती है परेशानी

आवेदन में उल्लेख किया गया कि नगर परिषद मानपुर चारों ओर से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र से घिरा हुआ है। ऐसे में आम निस्तार के लिए जंगल से जलाऊ लकड़ी प्राप्त करना नगरवासियों के लिए आसान नहीं है। विशेषकर किसी परिवार में मृत्यु होने पर दाह संस्कार के लिए आवश्यक लकड़ी की व्यवस्था करने में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

रवि सेन ने मांग की कि वन विभाग, नगर परिषद एवं राजस्व विभाग के समन्वय से मानपुर में निस्तार डिपो स्थापित किया जाए, जहां निर्धारित राशि जमा कर नगरवासी आवश्यकता के अनुसार जलाऊ लकड़ी प्राप्त कर सकें। इससे आम लोगों को सुविधा मिलने के साथ जंगल पर अनावश्यक निर्भरता भी कम हो सकेगी।

बंदरों के आतंक से परेशान नगरवासी

आवेदन में नगर के विभिन्न वार्डों में लाल मुंह वाले बंदरों के बढ़ते आतंक का भी मुद्दा उठाया गया। आरोप है कि बंदरों के कारण आए दिन लोग घायल हो रहे हैं तथा घरों में रखे सामान और फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। घरों की छतों एवं पेड़-पौधों पर बंदरों के झुंड रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रवि सेन के अनुसार, नगर परिषद की पूर्व बैठक में बंदरों को पकड़वाने संबंधी प्रस्ताव पारित किए जाने की जानकारी भी सामने आई थी, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। उन्होंने कलेक्टर से संबंधित विभागों के माध्यम से बंदरों को पकड़वाने की प्रभावी कार्रवाई कराने की मांग की है।

वार्ड 5 में पेयजल आपूर्ति पुन: शुरू कराने की मांग

वार्ड क्रमांक 5 में दूषित पानी की शिकायतों के बाद एसडीएम मानपुर एवं नगर परिषद अमले द्वारा पेयजल आपूर्ति बंद किए जाने का उल्लेख भी आवेदन में किया गया है। इसके बाद टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई, लेकिन समय पर टैंकर नहीं पहुंचने से वार्डवासियों को परेशानी होने की बात कही गई है। आवेदन में मांग की गई है कि वार्ड क्रमांक 5 स्थित पुरानी पंचायत टांका से पेयजल व्यवस्था का पुन: भौतिक सत्यापन कराया जाए। यदि जांच में पानी पीने योग्य पाया जाता है तो आवश्यक प्रक्रिया के बाद नल जलापूर्ति पुन: शुरू की जाए, ताकि वार्डवासियों को नियमित पेयजल उपलब्ध हो सके।

पहले भी दिए जा चुके हैं आवेदन

रवि सेन का कहना है कि निस्तार डिपो खोलने, बंदरों को पकड़वाने और पेयजल समस्या के निराकरण को लेकर उनके द्वारा पूर्व में भी जिला प्रशासन, नगर परिषद मानपुर, वन विभाग तथा जनसुनवाई के माध्यम से कई बार आवेदन दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद समस्याओं के स्थायी समाधान की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने का आरोप है। अब मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आयोजित शिविर में दिए गए आवेदन के बाद नगरवासियों की इन समस्याओं पर जिम्मेदार विभाग क्या कार्रवाई करते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इस बार आवेदन महज औपचारिकता बनकर न रह जाएं, बल्कि समस्याओं के स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।

संपादकीय

एक व्हाट्सएप चैट, स्क्रीनशॉट हत्या का आरोप और सुप्रीम कोर्ट का फैसला!



वैश्विक स्तरपर डिजिटल क्रांति ने मानव जीवन की कार्यशैली से लेकर अपराधों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया तक सब कुछ बदल दिया है।आज मोबाइल फोन,व्हाट्सएप चैट, ई-मेल,सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल लोकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार सामग्री जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं।लेकिन डिजिटल युग में एक बुनियादी सवाल लगातार गंभीर होता जा रहा है,क्या किसी मोबाइल फोन में मौजूद संदेश को हीकिसी व्यक्ति के अपराधी होने का निर्णायक प्रमाण मान लिया जाए? क्या किसी संदेश का तकनीकी रूप से भेजा जाना यह भी साबित कर देता है कि उसमें लिखी गई हर बात सच है? मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह बताना चाहूंगा कि इसी महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने नई चर्चा को जन्म दिया है। शुक्रवार दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को कुसुमलाल साव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हत्या के एक मामले में आरोपी की दोषसिद्धि रद्द करते हुए स्पष्ट किया कि विवादित व्हाट्सएप संदेश,जिनकी प्रामाणिकता और जानकारी के स्रोत की पुष्टि नहीं हुई थी,अपने आप में हत्या का दोष साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।यह निर्णयडिजिटल साक्ष्यों की विश्वसनीयता,गवाहों की भूमिका और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पूरी कड़ी स्थापित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।मीडिया में आई जानकारी के अनुसार क्रिमिनल अपील नंबर 4894 ऑफ़ 2026 एसएलपी(क्रल) नंबर 11542 ऑफ़ 2026 से उत्पन्न न्यायालय एवं पीठ भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई निर्णय की तारीख 13 अक्टूबर 2026 न्यूट्रल साइटेशन- 2026 आईं एनएससी 1148 इसलिए यह कहना अधिक सटीक होगा कि फैसला 13 अक्टूबर 2026 को सुनाया गया और इसकी चर्चा 23 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित समाचारों में भी हुई।बता दें कि यह पूरी जानकारी मीडिया से दी गई है।

साथियों बात अगर हम हत्या का मामला क्या था?व्हाट्सएप संदेशों ने कैसे खड़ा किया कानूनी सवाल? इसको समझने की करें तो, इस मामले की शुरुआत 9 फरवरी 2019 को हुई,जब सौरभ पांडा नामक व्यक्ति का शव एक खुले मैदान में मिला।शव के पास उसकी मोटरसाइकिल और रस्सी भी थी।पोस्टमार्टम के बाद मामला हत्या का मानकर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस जांच के दौरान अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर कुसुमलाल साव को इस अपराध से जोड़ने का प्रयास किया। जांच में अभियोजन पक्ष के दो गवाहों, जिन्हें न्यायालयीन रिकॉर्ड में पीडब्ल्यू-5 और पीडब्ल्यू-6 कहा गया, के मोबाइल फोन जब्त किए गए। फोरेंसिक जांच में उनके फोन के बीच 7 और 8 फरवरी 2019 की दरमियानी रात एक व्हाट्सएप संदेश मिलने की बात सामने आई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उस संदेश में मृतक और आरोपी के बीच कथित विवाद तथा मारपीट का उल्लेख था। अभियोजन ने इस संवाद को आरोपी की कथित संलिप्तता से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण आधार बनाया।इसके अतिरिक्त, आरोपी के घर से लोहे की रॉड, पेचकस, खून के निशान वाली शर्ट और खून लगी मिट्टी मिलने का दावा किया गया। निचली अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और धारा 201 (साक्ष्य मिटाने से संबंधित अपराध) के तहत दोषी ठहराया। हाईकोर्ट ने भी दोषसिद्धि बरकरार रखी।फ़िर इसके बाद आरोपी ने विश्वास से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

साथियों बात अगर हम अदालत ने व्हाट्सएप चैट को पर्याप्त सबूत क्यों नहीं माना? इसको समझनेकी करें तो इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि दोनों गवाहों ने कथित घटना के बारे में अभियोजन पक्ष के दावे का समर्थन नहीं किया। उन्होंने आरोपी और मृतक के बीच उस रात कथित झगड़े को अपनी आंखों से देखने की पुष्टि नहीं की। संदेश भेजने के आरोप से जुड़े गवाह ने यह भी कहा कि उसने ऐसा संदेश भेजा ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के सामने इसलिए केवल यह सवाल नहीं था कि मोबाइल फोन में संदेश मौजूद था या नहीं, बल्कि यह भी था कि संदेश किसने लिखा, वह किस जानकारी पर आधारित था और क्या उसमें वर्णित घटना वास्तव में हुई थी।न्यायालय ने माना कि पीडब्ल्यू-5 और पीडब्ल्यू-6 के बीच संदेशों का आदान-प्रदान यह साबित नहीं करता कि मृतक उस रात आरोपी के घर मौजूद था अथवा आरोपी ने उस पर हमला किया था। संदेश अधिकतम संदेह पैदा कर सकते थे, लेकिन संदेह और दोष सिद्ध होने के बीच महत्वपूर्ण अंतरहै।आपराधिक न्याय व्यवस्था में दोष सिद्धि के लिए अभियोजन को अपराध संदेह से परे साबित करना होता है।

साथियों बात अगर हम साक्ष्य अधिनियम की धारा 6- एक ही घटनाक्रम का हिस्सा होना क्यों जरूरी? इसको समझने की करें तो,इस निर्णय का कानूनी महत्व भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 6 की व्याख्या में भी है। यह प्रावधान सामान्यतः उन तथ्यों को प्रासंगिक बनाने से संबंधित है जो किसी विवादित तथ्य या घटना से इतने निकटता से जुड़े हों कि एक ही लेन-देन या घटनाक्रम का हिस्सा माने जा सकें। इसे अक्सर रेस गेस्टएके सिद्धांत के रूप में समझाया जाता है।अदालत ने पाया कि इस मामले में मौत का सही समय ठोस साक्ष्य से निर्धारित नहीं हो पाया था। इसलिए यह स्थापित करना कठिन था कि विवादित संदेश अपराध के समय या उसके आसपास भेजे गए थे और उसी घटनाक्रम का हिस्सा थे।धारा 7 के संदर्भ में भी अदालत ने स्पष्ट किया कि संदेश के तकनीकी रूप से एक फोन से दूसरे फोन तक पहुंचने की बात, उसमें वर्णित घटना की सत्यता को अपने आप साबित नहीं करती। संदेश भेजने वाले की जानकारी का स्रोत और उसके कथन का आधार जानना जरूरी था। यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना चाहिए- किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का अस्तित्व साबित करना और उस रिकॉर्ड में लिखी बात को सच साबित करना दो अलग-अलग प्रश्न हैं।

सब का पानी एक, सब की हवा एक
सब का मालिक एक



साहबजादा अब्दुल रशीद खान
प्रधान सम्पादक सच्चे दिन समूह

देश से शोहरत और दौलत पाकर विदेशों में बसती - भारतीय सेलिब्रिटीज



भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि भावनाओं, संस्कारों, संस्कृति और करोड़ों लोगों के सपनों का नाम है। दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाले इस देश की एक अनूठी विशेषता रही है कि यहाँ की जनता जिस प्रतिभा को अपना प्यार और समर्थन देती है, उसे सफलता के शिखर तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। चाहे क्रिकेट का मैदान हो, फिल्मी दुनिया हो, राजनीति हो, कला हो या सामाजिक क्षेत्र भारतीय जनमानस ने अनेक साधारण प्रतिभाओं को असाधारण पहचान दिलाकर विश्व मंच पर प्रतिष्ठित किया है। यह भारतीय नागरिकों का अपने देश की प्रतिभाओं के प्रति अपार प्रेम है, जुनून है या फिर दीवानगी कि वे किसी प्रतिभावान व्यक्ति को शून्य से शिखर तक पहुँचाकर दुनिया की प्रमुख हस्तियों में शामिल कर देते हैं। किसी छोटे गांव, कस्बे या सामान्य परिवार से निकलने वाला युवा जब अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ता है, तो देश के करोड़ों लोग उसकी सफलता में अपना सपना देखने लगते हैं। उसकी जीत पर जश्न मनाते हैं, उसकी असफलता पर दुखी होते हैं और उसकी एक झलक पाने के लिए घंटों प्रतीक्षा करते हैं। यही भारतीय जनता का प्रेम है, यही उसकी दीवानगी है और यही वह ताकत है, जो किसी खिलाड़ी, अभिनेता या कलाकार को सामान्य व्यक्ति से लोकप्रिय हस्ती बना देती है। लेकिन सवाल यह है कि जिस देश की जनता ने किसी व्यक्ति को पहचान, प्रतिष्ठा, दौलत और शोहरत के शिखर तक पहुँचाया, क्या उस देश के प्रति उसकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? जिस देश ने सिर आँखों पर बिठाया, क्या उस देश के प्रति भी कोई जिम्मेदारी नहीं? बेशक, दुनिया के हर नागरिक को अपना देश सबसे प्यारा लगता है और लगना भी चाहिए। दुनिया में अनेक ऐसी महान हस्तियां हुई हैं, जिन्होंने अपने वतन में प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद भी अपनी मातृभूमि से नाता नहीं तोड़ा। लेकिन पिछले दो-तीन दशकों में विशेषकर भारतीय सेलिब्रिटीज के बीच अपने देश से ख्याति और अपार धन-दौलत अर्जित करने के बाद विदेशों में बसने का चलन बढ़ता दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि जिस देश की जनता किसी व्यक्ति को सिर-आँखों पर बैठाकर उसे प्रसिद्धि के शिखर तक पहुँचाती है, क्या उस देश के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? जब किसी चर्चित हस्ती की सफलता का बड़ा आधार भारतीय जनता का प्रेम, देश का बाजार और यहाँ मिले अवसर हों, तब यह प्रश्न पूछना अनुचित नहीं कि उसकी सफलता में योगदान देने वाले समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी क्या है? लोकप्रियता की सीढ़ियां भारत में, आशियाना विदेशों में क्यों ? भारतीय जनता का प्यार केवल कमाई का साधन है या एक विश्वास भी?

भारत में क्रिकेट और फिल्मी दुनिया पर धन की जिस तरह बरसात होती है, वह किसी से छिपी नहीं है। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों ने खिलाड़ियों को करोड़ों रुपये के अनुबंध, विज्ञापन, लोकप्रियता और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसी तरह भारतीय दर्शकों ने फिल्मी कलाकारों को अपार सफलता दी है। दर्शकों की टिकटों पर खर्च की गई रकम, दर्शकों की संख्या, प्रशंसकों का समर्थन और देश के विशाल मनोरंजन बाजार ने अनेक हस्तियों के करियर को नई ऊँचाइयों दी हैं। ऐसे में यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि लोकप्रिय हस्तियाँ केवल अपनी कमाई और व्यक्तिगत सुविधाओं तक सीमित न रहें, बल्कि समाज के प्रति अपने दायित्वों को भी समझें। वे शिक्षा, खेल सुविधाओं, ग्रामीण प्रतिभाओं, गरीब बच्चों, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक विकास के लिए योगदान दें। अपनी लोकप्रियता का उपयोग देश की सकारात्मक छवि और नई पीढ़ी के निर्माण में करें। गांव-देहात या छोटे कस्बों में रहने वाला कोई लड़का या लड़की जब क्रिकेट अथवा फिल्मों में अपना भाग्य आजमाने निकलता है, तो भारतीय जनमानस ही उसकी प्रतिभा को पहचान कर उसे लोकप्रियता के शिखर तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाता है। अपने चहेते खिलाड़ी या अभिनेता-अभिनेत्री की एक झलक पाने के लिए प्रशंसक घंटों धूप-छाँव, भूख-प्यास और तमाम परेशानियों की परवाह किए बिना खड़े रहते हैं। यह दीवानगी केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अपने आदर्शों के प्रति लोगों का भावनात्मक जुड़ाव भी शामिल है। किसी सेलिब्रिटी की लोकप्रियता केवल उसकी निजी उपलब्धि नहीं होती। लाखों युवा उसे अपना आदर्श मानते हैं, उसकी जीवनशैली से प्रभावित होते हैं और उसकी सफलता को अपने भविष्य का सपना बनाते हैं। ऐसे में चर्चित हस्तियों के व्यवहार का सामाजिक प्रभाव सामान्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक होता है।

लेकिन विडंबना देखिए कि जिस देश की जनता किसी खिलाड़ी या फिल्मी हस्ती को अपार सम्मान, दौलत और शोहरत देती है, उसी देश की कुछ चर्चित हस्तियाँ बाद में विदेशों में स्थायी रूप से बसने का विकल्प चुन लेती हैं। फिल्मी दुनिया की अनेक अभिनेत्रियों ने विदेशों में विवाह करने के बाद वहाँ अपना घर बसाया है। कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों और अन्य हस्तियों ने भी विदेशों में निवास करने या विदेशी नागरिकता अपनाने का रास्ता चुना है। हालाँकि विदेश में रहने वाले प्रत्येक भारतीय को देशविरोधी ठहराना उचित नहीं है और न ही विदेश में बसना अपने आप में किसी अपराध की श्रेणी में आता है। फिर भी, जब कोई सेलिब्रिटी भारत में मिली लोकप्रियता और आर्थिक सफलता के बल पर अपना साम्राज्य खड़ा करने के बाद देश से स्थायी दूरी बना लेता है, तो उसके प्रशंसकों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या भारत से नाम, सम्मान और धन अर्जित करने वाली हस्तियों की अपने देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? क्या जिस जनता ने उन्हें प्रसिद्धि के शिखर तक पहुँचाया, उसके प्रति उनका कोई दायित्व नहीं बनता? यह प्रश्न किसी की निजी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का नहीं, बल्कि देश के प्रति कृतज्ञता, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय जुड़ाव की भावना को समझने का है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन, निवास और भविष्य के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन देश से मिली पहचान और सम्मान के प्रति आभार व्यक्त करना भी एक महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य है। देश की मिट्टी में जन्म लेकर, यहीं की परिस्थितियों में पले-बढ़े और भारतीय जनता के बीच अपनी पहचान बनाने वाले खिलाड़ी, अभिनेता और अभिनेत्रियाँ करोड़ों युवाओं के आदर्श बन जाते हैं। ऐसे में उनकी जीवनशैली और निर्णयों का समाज पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। जब युवा अपने आदर्शों को विदेशों में बसते देखते हैं, तो उनमें से कुछ के मन में भी देश छोड़कर विदेशों में आरामदायक जीवन बिताने की इच्छा प्रबल हो सकती है। हालाँकि युवाओं के विदेश जाने के पीछे रोजगार, शिक्षा, बेहतर अवसर और जीवनशैली जैसे अनेक कारण होते हैं; इसलिए इस प्रवृत्ति का पूरा दोष सेलिब्रिटीज पर डालना उचित नहीं होगा। फिर भी, लोकप्रिय हस्तियों के सामाजिक प्रभाव और उनकी जिम्मेदारियों पर गंभीर चर्चा आवश्यक है।

भारतीय सेलिब्रिटीज का विदेशों में बसना केवल भावनात्मक बहस का विषय नहीं होना चाहिए। यह भी देखना जरूरी है कि देश में प्रतिभाओं के विकास, रोजगार, खेल सुविधाओं, फिल्म निर्माण, अनुसंधान और उद्यमिता के लिए कितने बेहतर अवसर उपलब्ध हैं। यदि भारत में विश्व स्तरीय सुविधाएँ, सुरक्षित वातावरण, पारदर्शी व्यवस्था और पर्याप्त अवसर सुनिश्चित किए जाएँ, तो प्रतिभाशाली लोगों को अपने देश में ही काम करने और आगे बढ़ने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। देश से प्रतिभा का पलायन रोकने का स्थायी समाधान केवल भावनात्मक अपील में नहीं, बल्कि बेहतर नीतियों और अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण में निहित है। भारत की सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक सौहार्द, लोकतांत्रिक परंपराएँ और सामूहिक जीवन-मूल्य उसकी सबसे बड़ी शक्तियों में शामिल हैं।

वेस्ट मैनेजमेंट: कचरे से रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर



कचरा प्रबंधन अब केवल कूड़ा इकट्ठा करने और उसे ठिकाने लगाने तक सीमित नहीं रह गया है। यह रोजगार, उद्यमिता, नवाचार और पर्यावरण संरक्षण के नए अवसर प्रदान करने वाला एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। बढ़ती जनसंख्या, शहरों के विस्तार और उपभोग में वृद्धि के कारण घरों, उद्योगों, बाजारों तथा संस्थानों से निकलने वाले कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है। यदि इसका वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन किया जाए, तो यही कचरा मूल्यवान संसाधन और सतत आर्थिक विकास का आधार बन सकता है।

कचरे को खुले स्थानों पर फेंकना, लैंडफिल में जमा करना या जलाना पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्याएँ पैदा करता है। इससे वायु प्रदूषण, भूजल का दूषित होना, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है। इसके विपरीत, सुव्यवस्थित कचरा प्रबंधन इन समस्याओं को कम करने के साथ-साथ हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकता है।

कचरा प्रबंधन का मूल सिद्धांत यह है कि अलग-अलग प्रकार के कचरे का निपटान उनकी प्रकृति के अनुसार किया जाना चाहिए। घरेलू कचरे में जैविक पदार्थ, कागज, प्लास्टिक, काँच, धातुएँ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कचरा और अन्य अनुपयोगी वस्तुएँ शामिल होती हैं। यदि इन्हें स्रोत पर ही अलग-अलग कर दिया जाए, तो इनमें से अनेक वस्तुओं का पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण या नए उत्पाद बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है।

रसोईघरों, सब्जी मंडियों, होटलों और कृषि गतिविधियों से निकलने वाले जैविक कचरे से खाद तथा बायोगैस बनाई जा सकती है। जैविक खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने में मदद करती है। बायोगैस का उपयोग खाना पकाने, गर्मी उत्पन्न करने और कुछ औद्योगिक कार्यों में किया जा सकता है।

इसी प्रकार, कागज, प्लास्टिक, काँच और धातुओं को इकट्ठा करके, छाँटकर तथा संसाधित करके पुनर्चक्रण उद्योगों को उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे कचरा संग्रहकर्ताओं, परिवहन कर्मचारियों, मशीन संचालकों, तकनीकी विशेषज्ञों और उद्यमियों के लिए रोजगार पैदा होता है।

पुनर्चक्रण कचरे से आय अर्जित करने के सबसे उपयोगी क्षेत्रों में से एक है। युवा उद्यमी छोटे संग्रह केंद्र स्थापित कर सकते हैं, जहाँ अनुपयोगी सामग्री खरीदी जाए, उसकी छँटाई की जाए और उसे पुनर्चक्रण इकाइयों तक पहुँचाया जाए। पर्याप्त प्रशिक्षण और निवेश से प्लास्टिक, कागज तथा धातुओं के प्रसंस्करण का व्यवसाय भी शुरू किया जा सकता है।

प्लास्टिक कचरे से पुनर्चक्रित दाने बनाए जा सकते हैं, जिनका उपयोग कुछ नए उत्पादों के निर्माण में होता है। पुराने कागज से पुनर्चक्रित कागज और पैकेजिंग सामग्री तैयार की जा सकती है। धातुओं के कबाड़ को उपयोगी कच्चे माल में बदलकर विनिर्माण उद्योगों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

ऐसे व्यवसाय प्राकृतिक संसाधनों की बचत करते हैं और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। इस व्यवस्था में वस्तुओं और सामग्रियों को उपयोग के बाद फेंकने के बजाय यथासंभव लंबे समय तक उत्पादन प्रक्रिया में बनाए रखा जाता है। हालाँकि, पुनर्चक्रण के दौरान पर्यावरण और सुरक्षा संबंधी मानकों का पालन करना आवश्यक है।

ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि प्रधान समुदायों में जैविक कचरे के प्रबंधन से रोजगार की विशेष संभावनाएँ पैदा हो सकती हैं। किसान, स्वयं सहायता समूह, सहकारी संस्थाएँ और युवा उद्यमी कृषि अवशेषों, पशुओं के गोबर, रसोई के कचरे तथा बगीचों से निकलने वाली सामग्री का उपयोग करके खाद बनाने की इकाइयाँ स्थापित कर सकते हैं।

तैयार खाद किसानों, नर्सरियों, बागवानी केंद्रों और उद्यानों की देखभाल करने वाले व्यवसायों को बेची जा सकती है। छोटे बायोगैस संयंत्र उपयुक्त जैविक कचरे से नवीकरणीय ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। नगर निकायों, विद्यालयों, होटलों और आवासीय समितियों के सहयोग से स्थानीय स्तर पर कचरा प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। इससे परिवहन खर्च कम होगा और स्थानीय लोगों को काम मिलेगा।

डिजिटल तकनीक के तेजी से प्रसार के कारण मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टेलीविजन, बैटरियों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कचरा बढ़ रहा है। इस कचरे में तांबा, एल्युमीनियम और कुछ मूल्यवान धातुएँ होती हैं। लेकिन इसमें मौजूद हानिकारक पदार्थों के कारण गलत तरीके से निपटान करने पर मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुँच सकता है।

इस क्षेत्र में अधिकृत ई-वेस्ट संग्रह केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत, पुराने उपकरणों को फिर से उपयोग योग्य बनाने वाले व्यवसाय और विशेष पुनर्चक्रण इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं। मरम्मत और नवीनीकरण से उपकरणों का जीवन बढ़ता है तथा लोगों को कम कीमत पर तकनीक उपलब्ध हो सकती है।

डिजिटल बैंकिंग में भरोसे का संकट

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के लगभग चार हजार ग्राहकों की निजी जानकारी जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, ईमेल, आवासीय पता, ग्राहक पहचान संख्या और ऋण से जुड़े विवरण डार्क वेब पर सामने आने की खबर ने देश की बैंकिंग व्यवस्था के सामने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। जिस बैंक पर करोड़ों लोग अपनी जीवनभर की बचत के लिए भरोसा करते हैं, यदि उसके ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित नहीं रह पाती तो डिजिटल बैंकिंग पर लोगों का विश्वास कैसे बना रहेगा?

यह घटना केवल तकनीकी सुरक्षा से जुड़ा मामला नहीं है। इसका सीधा संबंध ग्राहकों की गोपनीयता, वित्तीय सुरक्षा और बैंकों की जवाबदेही से है। व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग भविष्य में वित्तीय धोखाधड़ी का कारण बन सकता है। किसी साइबर अपराधी के पास ग्राहक का नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि और ऋण आवेदन का विवरण हो तो वह बैंक अधिकारी बनकर विश्वास हासिल करने का प्रयास कर सकता है। वह ग्राहक को ऋण स्वीकृति, केवाईसी अपडेट या खाते की सुरक्षा के नाम पर धोखा दे सकता है। इस प्रकार निजी जानकारी की चोरी आर्थिक नुकसान का रास्ता खोल सकती है।

आज बैंक केवल जमा और ऋण देने वाले संस्थान नहीं रह गए हैं। उनके पास ग्राहकों की आय, संपत्ति, व्यवसाय, पारिवारिक विवरण, लेनदेन और वित्तीय व्यवहार से जुड़ी व्यापक जानकारी रहती है। यह जानकारी बैंकिंग सेवाओं को सुविधाजनक बनाती है, लेकिन इसके गलत हाथों में पहुंचने की कीमत बहुत अधिक हो सकती है। दूसरे देशों का अनुभव हमारे लिए उपयोगी सबक प्रस्तुत करता है। अमेरिका में 2019 में कैपिटल वन बैंक से जुड़ी एक बड़ी डाटा चोरी सामने आई थी। इससे अमेरिका के लगभग 10 करोड़ और कनाडा के लगभग 60 लाख लोग प्रभावित हुए थे। इससे स्पष्ट होता है कि साइबर सुरक्षा में कमजोरी को केवल तकनीकी चूक मानकर अनदेखा नहीं किया जा सकता। बैंक प्रबंधन की जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यूरोपीय संघ ने व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा के गंभीर जोखिम वाले डाटा उल्लंघन की सूचना नियामक को सामान्यतः 72 घंटे के भीतर देने की व्यवस्था की है। तकनीकी सेवाएं किसी बाहरी कंपनी को सौंप देने से बैंक की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती।

सिंगापुर ने भी फिशिंग धोखाधड़ी के कुछ निर्धारित मामलों में बैंकों और दूरसंचार कंपनियों की साझा जिम्मेदारी तय करने वाला ढांचा विकसित किया है। इसका उद्देश्य केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि वित्तीय संस्थानों को धोखाधड़ी रोकने के लिए अधिक जिम्मेदार बनाना है। भारत ने डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और 2025 में अधिसूचित नियमों के माध्यम से महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हालांकि डाटा उल्लंघन की सूचना देने सहित कई प्रमुख प्रविधानों का लागू होना अभी शेष है।

देश के तीन आईआईटी में मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग का संगम: डॉक्टर नहीं, मेडिकल इंजीनियर तैयार करने की पहल

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान तेजी से तकनीक पर निर्भर होता जा रहा है। आज अस्पतालों में सीटी स्कैन, एमआरआई , आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , रोबोटिक्स, बायो-सेंसर और अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक मशीनों का उपयोग बढ़ रहा है। ऐसे में चिकित्सा और इंजीनियरिंग के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है।

इसी दिशा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी कानपुर चिकित्सा विज्ञान तथा इंजीनियरिंग को एक साथ लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इन संस्थानों का उद्देश्य ऐसे विशेषज्ञ तैयार करना है जो मानव शरीर की कार्यप्रणाली और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की तकनीक–दोनों को समझ सकें।

कल्पना कीजिए कि किसी मरीज की सीटी स्कैन रिपोर्ट में एक हिस्सा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर को यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि इसका कारण मशीन की तकनीकी समस्या है या मरीज की बीमारी। दूसरी ओर, मशीन बनाने वाले इंजीनियर को उस चिकित्सकीय परिस्थिति की पूरी जानकारी नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में चिकित्सा और तकनीक, दोनों का ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे डॉक्टरों और इंजीनियरों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने, मशीनों की उपयोगिता बढ़ाने और रोगों की पहचान को अधिक सटीक बनाने में मदद कर सकते हैं।

हालांकि, ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टरों और पारंपरिक इंजीनियरों का स्थान लेने के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार किए जाते हैं।

आईआईटी मद्रास ने मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विशेष शैक्षणिक पहल की है। संस्थान का उद्देश्य चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग और आधुनिक तकनीक के बीच सहयोग को मजबूत करना है। यहां मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग से संबंधित पाठ्यक्रमों में मानव शरीर की कार्यप्रणाली, गणितीय मॉडलिंग, क्लिनिकल न्यूरोसाइंस और मेडिकल इमेजिंग जैसे विषय शामिल हैं। इन विषयों के माध्यम से विद्यार्थियों को यह समझने का अवसर मिलता है कि इंजीनियरिंग के सिद्धांतों का उपयोग मानव शरीर, रोगों की पहचान और चिकित्सा अनुसंधान में किस प्रकार किया जा सकता है।

आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामकोटि का मानना है कि तकनीकी संस्थानों को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। चिकित्सा उपकरणों और स्वास्थ्य तकनीक के क्षेत्र में देश की क्षमता बढ़ाना भारत की दीर्घकालिक जरूरत है।

आईआईटी खड़गपुर ने चिकित्सा विज्ञान और तकनीक के समन्वय के क्षेत्र में लंबे समय से काम किया है। यहां 2001 में स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी।

संस्थान का एमएमएसटी कार्यक्रम विशेष रूप से ऐसे चिकित्सकों के लिए तैयार किया गया था, जो इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान के ज्ञान के माध्यम से अपने चिकित्सा कौशल को और बेहतर बनाना चाहते हैं। आईआईटी खड़गपुर ने अपने परिसर में डॉ. बी. सी. रॉय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से चिकित्सा सुविधाओं और अनुसंधान को आगे बढ़ाने की दिशा में भी काम किया है। यहां मेडिकल इमेजिंग, मॉलिक्यूलर इमेजिंग, बायोमटेरियल्स, इम्प्लांट्स, बायोफिजिक्स, कैंसर की शुरुआती पहचान, इम्यूनो-टेक्नोलॉजी और क्लिनिकल बायोमार्कर जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान की संभावनाएं हैं।

इन प्रयासों का व्यापक उद्देश्य चिकित्सा क्षेत्र में नई तकनीकों के विकास को बढ़ावा देना और अनुसंधान को वास्तविक मरीजों की जरूरतों से जोड़ना है।

आईआईटी कानपुर का गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी चिकित्सा शिक्षा, उच्च स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और इंजीनियरिंग तकनीक को एक मंच पर लाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इस प्रकार के संस्थानों में भविष्य की चिकित्सा तकनीकों के विकास, उन्नत डायग्नोस्टिक प्रणालियों, मेडिकल रोबोटिक्स, बायोमेडिकल उपकरणों और एआई आधारित स्वास्थ्य सेवाओं पर काम करने की व्यापक संभावनाएं हैं।

प्रदेश में उन्नत पैकेजिंग एवं परीक्षण, सुदृढ़ फैबलेस इको सिस्टम तथा सेमी कंडक्टर विनिर्माण के विकास पर हुआ मंथन

इन्दौर। मध्यप्रदेश सेमी कंडक्टर समिट2026 इंदौर में विभिन्न उद्योगपतियों एवं सेमी कंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों की सहभागिता से तीन विषयों पर पैनल डिस्कशन हुआ। इनमें मध्यप्रदेश को उन्नत पैकेजिंग एवं परीक्षण का केंद्र बनाने, प्रदेश में सुदृढ़ फैबलेस इको सिस्टम के निर्माण तथा सेमी कंडक्टर विनिर्माण एवं आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया।

विशेषज्ञों ने चिप डिजाइन से लेकर उत्पाद विकास, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग एवं परीक्षण तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं पर अपने विचार रखे। डिस्कशन में औद्योगिक अधोसंरचना, अनुकूल नीतियों, वित्तीय संसाधनों, बाजार की उपलब्धता, उद्योग एवं शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग तथा उन्नत अनुसंधान एवं कौशल विकास की आवश्यकता प्रमुखता से रखी गई।

उन्नत पैकेजिंग एवं परीक्षण के लिए अधोसंरचना और स्थानीय क्षमताओं के विकास पर जोर-मध्यप्रदेश को उन्नत पैकेजिंग एवं परीक्षण का केंद्र बनाना÷ विषय पर आयोजित पैनल चर्चा का संचालन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री चरण गुरुमूर्ति ने किया। डिस्कशन में विशेषज्ञों ने प्रदेश में उद्योग स्थापना के लिए उपलब्ध सुविधाओं, तकनीकी संस्थानों, नीतिगत सहयोग तथा पैकेजिंग उद्योग की आवश्यकताओं पर विचार रखे।

पारस सेमी कंडक्टर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संतोष कुमार ने कहा कि मध्यप्रदेश सेमी कंडक्टर उद्योग की स्थापना के लिए आदर्श स्थल है। इंदौरङ्कउज्जैन कॉरिडोर को सेमी कंडक्टर जोन के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां कार्गो एवं लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के साथ संयंत्र स्थापना के लिए भूमि, जल एवं बिजली की व्यवस्था उपलब्ध है। प्रदेश में इस उद्योग के लिए आवश्यक इको सिस्टम एवं आपूर्ति श्रृंखला भी विकसित हो रही है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश शासन का सहयोग, त्वरित निर्णय प्रक्रिया तथा सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से शीघ्र स्वीकृतियां मिलने से उद्योग स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण बन रहा है।

सीईओ श्री कुमार ने पैकेजिंग उद्योग की अधोसंरचना के विकास के संबंध में कहा कि संयंत्रों के डिजाइन एवं निर्माण के लिए प्रारंभ से अंत तक समग्र इंजीनियरिंग सेवाएं उपलब्ध कराने वाली वैश्विक कंपनियों की विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सकता है। इन कंपनियों और स्थानीय ठेकेदारों के समन्वय से डिजाइन एवं निर्माण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।

आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स की मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी सुश्री अपूर्वा राउत ने कहा कि सेमी कंडक्टर पैकेजिंग उद्योग के विकास के लिए उपयुक्त सोच एवं प्रयासों में निरंतरता आवश्यक है और मध्यप्रदेश में ये दोनों विशेषताएं मौजूद हैं। उन्होंने बिजली की उपलब्धता को इस उद्योग की महत्वपूर्ण आवश्यकता बताते हुए कहा कि मध्यप्रदेश का पावर सरप्लस राज्य होना इसे सेमी कंडक्टर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण स्थान बनाता है।

सुश्री राउत ने कहा कि पैकेजिंग उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बड़े पैमाने पर कार्गो एवं लॉजिस्टिक्स संचालन की क्षमता विकसित करना तथा प्रमुख शहरों से बेहतर संपर्क सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने पैकेजिंग डिजाइन के क्षेत्र में आईआईटी एवं अन्य विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए जाने का सुझाव दिया।

श्री सुधीर नाईक ने प्रदेश में उपलब्ध तकनीकी प्रतिभाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आईआईटी इंदौर जैसे प्रगतिशील संस्थान एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालय मध्यप्रदेश को तकनीकी प्रतिभा के केंद्र के रूप में विकसित करने का आधार प्रदान करते हैं।

खुद की जान को जोखिम में डालकर दूसरों के प्राण बचाती है पुलिस- मुख्यमंत्री डॉ. यादव



इन्दौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पुलिस के जवान से लेकर अधिकारी तक लगातार बिना थके परिश्रम और ईमानदारी के साथ कार्य करते है। खुद की जान को जोखिम में डालकर दूसरों के प्राण बचाने का नाम है पुलिस। पुलिस के जवान साहस के साथ निष्पक्षता के साथ अपनी ड्यूटी निभाते है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस के जवान सेवा, सुरक्षा और परिश्रम में हमेशा आगे रहतें है। ऐसे पुलिसकर्मियों को उनके सेवा और साहसिक कार्यों के लिये सम्मानित किया जाना गर्व की बात है। मुख्यमंत्री डॉ.यादव शुक्रवार को इंदौर के होटल पार्क में ÷खाकी के जज्बे को पत्रिका का सलाम÷ आयोजित कार्यक्रम में अपना सम्बोधन दे रहे थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 30 से अधिक ऐसे पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया, जिन्होंने सेवा में रहते हुए साहसिक कार्य किये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्मानित पुलिसकर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि वे इस तरह के कार्य करते हुए समाज को सदैव प्रेरणा देते रहे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की भर्तियां की है तथा नई भर्तियां और की जायेंगी। साथ ही वर्षों से रुकी पदोन्नति पुन- प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्मान समारोह के दौरान अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सयोगितागंज थाने के आरक्षक लाल साहब को मंच से नीचे उतरकर सम्मानित किया। आरक्षक लाल साहब अपने पैरों में तकलीफ के कारण मंच पर चढ़ने में असमर्थ थे। कार्यक्रम में शिक्षाविद डॉ. स्वप्निल कोठारी ने कहा कि साहस जब ईमानदारी के साथ मिल जाता है, तो वह कहानी दूसरों के लिये प्रेरणा बन जाती है। पत्रिका के विकास यात्रा के बारे में जानकारी संपादक अनिल कर्मा ने दी।

कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक मधु वर्मा, रमेश मेंदोला, गोलू शुक्ला, संभागायुक्त भास्कार लाक्षाकार, आईजी अनुराग, पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर शिवम वर्मा, गौरव रणदिवे, सुमित मिश्रा सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी एवं उनके परिजन तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

इंदौर के झोन क्रमांक-3 पर मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत विशाल शिविर आयोजित

इन्दौर। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को स्काउट ग्राउंड चिमनबाग झोन क्रमांक-3 में विशाल जन विश्वास शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कलेक्टर श्री शिवम वर्मा, निगम आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल, महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, विधायक श्री गोलू शुक्ला, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हिमांशु प्रजापति, स्मार्ट सिटी के सीईओ श्री अर्थ जैन, एसडीएम श्री घनश्याम धनगर सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने सहभागिता की। शिविर में अधिकारियों ने नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी तथा उनके त्वरित निराकरण के लिये संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। शिविर में विभिन्न शासकीय योजनाओं के प्रात्र हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किये गये। अभियान के तहत प्रशासनिक अधिकारियों ने शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही विभिन्न विकास कार्यों, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और नागरिकों को मिल रही सुविधाओं की मैदानी स्थिति की जानकारी प्राप्त की।

कलेक्टर श्री वर्मा ने किया शासकीय सांदीपति अहिल्याश्रम विद्यालय का किया निरीक्षण- मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत कलेक्टर श्री वर्मा ने पोलोग्राउंड स्थित शासकीय सांदीपनि अहिल्याश्रम कन्या विद्यालय का निरीक्षण कर छात्राओं के लिये उपलब्ध शिक्षण व्यवस्था और केन्द्र के बारे में जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, विधायक श्री गोलू शुक्ला, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हिमांशु प्रजापति एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री वर्मा ने छात्राओं के साथ संवाद कर उनसे शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान संस्था के प्राचार्य ने बताया कि छात्राओं ने एटीएम का आधुनिक मॉडल बनाया। कलेक्टर श्री वर्मा ने छात्राओं के कार्यों की सराहना की और उन्हें आगे बढ़ने के लिये प्रोत्साहित किया। इस मौके पर अधिकारियों ने विद्यालय की समस्त कक्षाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

शिविर स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिये मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत यह विशाल शिविर आयोजित किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों की विभिन्न समस्याओं का मौके पर त्वरित निराकरण करना है। महापौर श्री भार्गव ने कहा कि अब संबंधित विभागों के अधिकारियों का दायित्व है कि वे नागरिकों की समस्याओं को न केवल संवेदनशीलता के साथ सुने बल्कि उसका समाधान भी करें। शिविर स्थल पर अधिकारियों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना एवं अन्य योजनाओं के हितलाभ हितग्राहियों को वितरित किये।

शिविर स्थल पर मुसाखेड़ी निवासी हितग्राही शिवम ओझा ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्राप्त ऋण से फूटवेयर दुकान से आमदनी बढ़ गई। शिवम ने कहा कि यह सब राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं से संभव हुआ है। दुकान के लिये अब मुझे अधिक ऋण लेने की पात्रता मिल जायेगी। कार्यक्रम में एमआईसी सदस्य श्री अभिषेक बबलू शर्मा और श्री मनीष शर्मा एवं क्षेत्रीय पार्षद उपस्थित थे।

शिविर स्थल पर पशुपालन डेयरी एवं डेयरी विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित विभिन्न शासकीय विभागों के स्टॉल लगाये गये। साथ ही शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित की गई।

150 करोड़ की विवादित जमीन में लोकायुक्त के रडार पर फिरोज खान, साथी SI शकील कुरैशी का नाम भी आया सामने



इंदौर। मगरखेड़ा (सांवेर रोड़) की विवादित जमीन में फिरोज खान की घेराबंदी शुरू हो गई है। फिरोज ने रसूख और वर्दी का डर बता कर किसान परिवार पर दबाव बनाया था। उसके साथ पदस्थ रहा एक एसआई शकील कुरैशी का नाम भी स्वजन ने लोकायुक्त को बताया है। उसका वीडियो भी सामने आ गया है। लोकायुक्त पुलिस के अनुसार जमीन कस्तुरी बाई के नाम की है।

करीब 150 करोड़ रुपये है जमीन की कीमत- करीब 150 करोड़ रुपये कीमती इस जमीन के सौदे में फिरोज खान गवाह के रुप में दर्ज है। सौदे के बाद कस्तुरी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इस दौरान फिरोज ने दबाव बनाकर कस्तुरी के स्वजन से मुलाकात पर रोक लगा दी। उस वक्त शकील वर्दी में अस्पताल गया था। लोकायुक्त के अनुसार फिरोज की महिला मित्र रोशनी वर्मा के साथ रानू,संतोष और नफीस पहले ही जांच के घेरे में आ चुके है। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के निलंबित प्रधान आरक्षक चालक फिरोज खान की संपत्तियों का ब्योरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोकायुक्त की जांच में हर दिन नई संपत्ति की जानकारी सामने आ रही है। शुक्रवार को देवास के आदर्श नगर में दो प्लॉट का पता चला। ये दोनों प्लॉट फिरोज खान की मां वहीदा खान के नाम पर खरीदे गए थे।

अब तक की जांच में फिरोज खान और उसके परिवार से जुड़ी प्लाट, कृषि भूमि, फ्लैट और मकानों सहित करीब 50 संपत्तियों की जानकारी सामने आ चुकी है। इन संपत्तियों का अनुमानित बाजार मूल्य 66 करोड़ रुपये से अधिक बताया जा रहा है। लोकायुक्त इन संपत्तियों के दस्तावेज, खरीद की प्रक्रिया और रकम के स्रोत की पड़ताल कर रहा है।

एसपी डा.राजेश सहाय के अनुसार फिरोज खान के ठिकानों पर लोकायुक्त ने 14 अक्टूबर सर्च की कार्रवाई की थी। इसके बाद से संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों और अन्य जानकारियों की जांच जारी है। कार्रवाई में लोकायुक्त ने 66 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति की जानकारी निकाल ली है।

गुरुवार तक निलामी में खरीदे मकानों को जोड़ कर 48 संपत्ति की गिनती की गई थी। शुक्रवार को आदर्श नगर के नए दो प्लॉट मिल भी मिल गए और इस तरह से आंकड़ा 50 तक पहुंच गया। डीएसपी सुनील तालान के मुताबिक गाइड लाइन के अनुसार तो इनकी कीमत 20 करोड़ है लेकिन बाजार भाव 66 करोड़ से अधिक है। लोकायुक्त की जांच का अहम पहलू यह है कि फिरोज खान और उसके परिवार के नाम पर मिली संपत्तियों को खरीदने के लिए रकम कहां से आई।

जांच पिपलरावा में आरा मशीन और खाते में लाखों मिले- डीएसपी सुनील तालान के अनुसार फिरोज का पिपलरावा (देवास) में लकड़ी का कारखाना है। उसमें भी करीब 8 लाख रुपये कीमती आरा मशीन मिली है। पुलिस को फिरोज के विभिन्न बैंकों में 22 खाते मिलें थे। 17 खातों की जानकारी मिल चुकी थी। शुक्रवार को उसकी फर्म महाराजा रियल एस्टेट का स्टेटमेंट मिला तो उसमें 9 लाख रुपये जमा मिलें है।

पीटीसी से लापता फिरोज ने अग्रिम जमानत मांगी- लंबे समय से गैर हाजिर और छापे के बाद गायब चल रहे फिरोज ने गिरफ्तारी के डर से अग्रिम जमानत मांगी है। फिरोज ने वकील के माध्यम से जिला कोर्ट में शुक्रवार को अर्जी दायर कर दी। कोर्ट ने लोकायुक्त से रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के अनुसार अफसर फिरोज की जमानत का विरोध करेंगे।

इंदौर एयरपोर्ट का नया विंटर शेड्यूल लागू, बैंकॉक, गोंदिया और जोधपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स, जबलपुर से टूटेगा संपर्क



इंदौर। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से 25 अक्टूबर से लागू होने जा रहे विंटर शेड्यूल में हवाई सेवाओं का नया समीकरण बनेगा। बैंकाक, गोंदिया और जोधपुर के लिए सीधी उड़ानों की शुरुआत होगी, तो दूसरी ओर जबलपुर से हवाई संपर्क टूट जाएगा। नए शेड्यूल में अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ घरेलू उड़ानों के विकल्प भी बदलेंगे।

विंटर शेड्यूल का सबसे अहम आकर्षण बैंकॉक के लिए दूसरी अंतरराष्ट्रीय उड़ान होगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस 2 दिसंबर से इस रूट पर नई उड़ान शुरू करेगी, जो सप्ताह में चार दिन संचालित होगी। हालांकि विंटर शेड्यूल में इस उड़ान का शेड्यूल है, लेकिन कंपनी ने अभी इसकी बुकिंग शुरू नहीं की है। यह उड़ान इंदौर से सुबह 9.40 बजे जाएगी और शाम वापस इंदौर आएगी।

इसके शुरू होने पर इंदौर से विदेश जाने वाले यात्रियों को दूसरी अंतरराष्ट्रीय उड़ान मिलेगी। अभी यूएई के अबूधाबी के लिए सीधी उड़ान संचालित होती है। यह उड़ान अभी रात्रि में 7.50 बजे रवाना होती है और रात्रि में वापस आती है, लेकिन 25 अक्टूबर से सुबह 8.40 बजे रवाना होगी और शाम को वापस इंदौर आएगी। इससे यात्रियों को रात्रि जागरण करने से राहत मिलेगी।

अहमदाबाद के लिए बढ़ेंगी उड़ानें- इंडिगो अहमदाबाद रूट पर तीसरी उड़ान शुरू करेगी। इससे इस व्यस्त रूट पर यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। वहीं गोवा और पुणे के रास्ते कोच्चि पहुंचने के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट की सुविधा भी मिलेगी। इससे इंदौर से केरल जाने वाले यात्रियों को फायदा होगा। गोवा और पुणे होकर वे यहां पर पहुंच सकेंगे और उनको उड़ान बदलने की आवश्यकता नहीं होगी।

मुंबई-दिल्ली की उड़ानों में बदलाव- विंटर शेड्यूल में मुंबई और दिल्ली रूट पर कुछ उड़ानें बंद होंगी, जबकि कुछ उड़ानों की संख्या बढ़ेगी। दिल्ली रूट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की चार में से तीन उड़ानें रह जाएंगी। वहीं मुंबई रूट पर दो की अपेक्षा तीन उड़ानें संचालित होंगी। दिल्ली रूट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की दो उड़ानें संचालित होती हैं, लेकिन 25 से एक ही उड़ान रह जाएगी। ऐसे में यात्रियों को टिकट बुक करने से पहले नया शेड्यूल देखना होगा। वहीं जबलपुर की उड़ान बंद होगी, इससे यात्रियों का हवाई संपर्क टूट जाएगा।

राउंड टेबल चर्चा में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा–उद्योग सहयोग और सेमी कंडक्टर कंपनियों के विकास पर हुआ मंथन



इन्दौर। मध्यप्रदेश को सेमी कंडक्टर एवं उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मध्यप्रदेश सेमी कंडक्टर समिट-2026 के प्रथम दिवस तीन राउंड टेबल मीट हुई। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमी कंडक्टर क्षेत्र में शिक्षा एवं उद्योग के बीच सहयोग तथा फैबलेस, प्रोडक्ट एवं आईपी कंपनियों से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। चर्चाओं में उद्योग जगत, तकनीकी विशेषज्ञों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर प्रदेश में सेमी कंडक्टर इको सिस्टम के विकास, निवेश की संभावनाओं, कौशल विकास और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के संबंध में सुझाव दिए।

प्रथम राउंड टेबल चर्चा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, तकनीकी सुविधाओं और उद्योगों में एआई के उपयोग पर विचार-विमर्श किया गया। चर्चा का उद्देश्य एआई एवं सेमी कंडक्टर क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच संवाद को बढ़ावा देना तथा प्रदेश में इन तकनीकों के विकास की संभावनाओं पर विचार करना था।

प्रेसीडेंट, ज्वाइंट रोल ऑफ आईईएसए एंड सेमी इण्डिया, श्री अशोक चंडाक तथा सिनॉप्सिस के सीनियर डायरेक्टर श्री माधवेंद्र शान भटनागर सहित अन्य प्रतिभागियों ने एआई एप्लीकेशन, नेटवर्क, अनुसंधान, नवाचार और कुशल मानव संसाधन विकास से जुड़े विषयों पर अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किए।

द्वितीय राउंड टेबल में सेमी कंडक्टर क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल मानव संसाधन तैयार करने तथा शैक्षणिक संस्थानों एवं उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। विद्यार्थियों को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण देने, विशेष पाठ्यक्रम विकसित करने और चिप डिजाइन एवं डिजाइन वेरिफिकेशन जैसे क्षेत्रों में तकनीकी दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया गया।

राउंड टेबल में मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, उद्योगों और संबंधित सरकारी विभागों को एक मंच पर लाकर राज्य स्तरीय सेमी कंडक्टर अकादमिक कंसोर्टियम स्थापित करने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। इसके साथ ही स्टार्ट अप को प्रोत्साहन, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास तथा अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने संबंधी चर्चा की गई।

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के वाइस चेयरमैन श्री राजीव दीक्षित ने मध्यप्रदेश सरकार की सेमी कंडक्टर इको सिस्टम विकसित करने की पहल को विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने उपस्थित प्रतिभागियों को मध्यप्रदेश सेमी कंडक्टर पॉलिसी-2025 के प्रावधानों की जानकारी दी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के कुलगुरु श्री राकेश सिंघल ने स्थानीय स्तर पर शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के सहयोग से अकादमिक कंसोर्टियम विकसित करने पर जोर दिया।

कलेक्टर के निर्देश पर वी वन अस्पताल की अपंजीकृत सोनोग्राफी मशीन सीलबंद



इन्दौर। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशानुसार इंदौर स्थित वी वन अस्पताल (ए यूनिट ऑफ मेडिहील हेल्थकेयर प्रा. लि.), गीता भवन चौराहा में पंजीयन प्रमाण-पत्र में दर्ज मशीन के अतिरिक्त पाई गई एक अन्य सोनोग्राफी मशीन को सीलबंद करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही अस्पताल संचालक को नोटिस जारी कर नियमानुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

बताया गया कि अस्पताल का पीसीपीएनडीटी पंजीयन क्रमांक 767 है। कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देश पर 23 अक्टूबर 2026 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी के निर्देशन में निरीक्षण दल द्वारा अस्पताल का निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण के दौरान पंजीयन प्रमाण-पत्र में दर्ज मशीन के अतिरिक्त स्टोर रूम में एक अन्य सोनोग्राफी मशीन पाई गई।

कलेक्टर श्री वर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल संबंधित मशीन को सीलबंद करने के निर्देश दिए। निर्देशों के पालन में डॉ. दिव्यानी अहरवाल एवं श्रीमती दीपमाला बामने को मौके पर भेजकर अपंजीकृत मशीन को सीलबंद कराया गया।

इसके साथ ही अस्पताल संचालक को नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

संक्षिप्त समाचार

कमिश्नर ने आंगनवाड़ी केंद्र बैरानिया का किया निरीक्षण

बैढन। नगर परिषद बरगवां में आयोजित जन विश्वास अभियान शिविर में शामिल होने आए रीवा संभाग के कमिश्नर शीलेन्द्र सिंह एवं प्रभारी कलेक्टर संघप्रिय ने ग्राम बैरानिया स्थित आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र में उपलब्ध व्यवस्थाओं, पोषण संबंधी गतिविधियों एवं अभिलेखों का जायजा लेते हुए आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध व्यवस्थाओं, पोषण वाटिका, पोषण आहार, उपस्थिति पंजी, हाइट-वेट पंजी, दवाइयों की उपलब्धता पंजी तथा टीएचआर पंजी का अवलोकन किया। पंजियों का व्यवस्थित संधारण नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी अभिलेखों को नियमित एवं व्यवस्थित रूप से संधारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र में बच्चों की कम उपस्थिति पर भी नाराजगी जाहिर की।

जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित

बैढन। देवसर विधान सभा क्षेत्र के माड़ा तहसील अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार शासकीय महाविद्यालय माड़ा के तत्वावधान में माड़ा स्थित सामुदायिक भवन में जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रातः 11 बजे से आयोजित इस प्रतियोगिता में सिंगरौली जिले के विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में देवसर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ.राजेंद्र मेश्राम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शासकीय महाविद्यालय माड़ा के प्राचार्य डॉ. गोविंद बाथम ने की। मंच पर जिले के वरिष्ठ खेल अधिकारी डॉ. विनोद राय एवं डॉ. उमाकांत सिंह भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा भगवान हनुमान की पूजा-अर्चना के साथ किया गया।

जनजातीय बहुल ग्राम में एयरटेल का मोबाइल टावर स्थापित

बैढन। सिंगरौली जिले के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे दूरस्थ आदिवासी बहुल गांव बासी बेरदहा में पहली बार मोबाइल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध हुई है। अदाणी नेचुरल रिसोर्सेज की पहल पर एयरटेल का मोबाइल टावर स्थापित होने से बासी बेरदहा और आसपास के गांवों के हजारों ग्रामीणों को मोबाइल नेटवर्क एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी का लाभ मिल सकेगा।इससे ग्रामीणों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं और अन्य आवश्यक ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। धिरौली परियोजना के आसपास स्थित इन गांवों में अब तक मोबाइल नेटवर्क के अभाव में ग्रामीणों को रोजमर्रा के कई जरूरी कार्यों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मोबाइल टावर की स्थापना से अब शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को इन समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है। इसी तरह, नेटवर्क की कमी के कारण सरकारी योजनाओं से संबंधित ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण, ओटीपी सत्यापन और लाभार्थियों के विवरण को अपडेट करने जैसे कार्य भी प्रभावित होते थे।

बुंदेलखंड को विंध्य से जोड़ने वाली पहली ट्रेन का शुभारम्भ

उपमुख्यमंत्री व सांसद ने दिखाई मेमू ट्रेन को हरी झंडी





- रेल का सपना हुआ साकार
- चुरहट से पहली बार चलने लगी मेमू ट्रेन

सीधी (ब्यूरो)

जिले के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आजादी के काफी अर्से बाद सीधी की धरती चुरहट से मेमू ट्रेन का सफल संचालन शनिवार को उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला एवं सांसद डॉ. राजेश मिश्रा द्वारा हरी झंडी दिखाकर संचालन किया गया। इस दौरान चुरहट में लोगों की काफी भीड़ रही। सफल संचालन को लेकर क्षेत्रवासियों ने डिप्टी सीएम एवं सांसद को बधाई भी दिए हैं। साथ ही यह उम्मीद है कि अब नए ट्रेनों का भी संचालन शुरू हो सकता है।

विंध्य क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में 24 अक्टूबर 2026 का दिन ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ। सतना-देवेंद्रनगर के 53 किलोमीटर तथा रीवा-चुरहट के 65 किलोमीटर रेलखंडों का लोकार्पण किया गया। साथ ही देवेंद्रनगर-चुरहट ट्रेन सेवा का शुभारंभ हुआ। इस उपलब्धि के साथ सीधी जिले का रामपुर नैकिन-चुरहट क्षेत्र पहली बार रेल सेवा से जुड गया है। इससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन का नया साधन मिलने के साथ व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सीधी सांसद डॉ. राजेश मिश्रा और रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने सहभागिता की। नागौद से नगरीय विकास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी, खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा, सतना सांसद गणेश सिंह तथा नागौद विधायक नागेंद्र सिंह ने भी वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।

जिले में लिखी जा रही विकास की गाथा - डॉ. राजेश मिश्रा

सीधी सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा कि आज जिले में विकास की गाथा लिखी जा रही है और हम सभी इस गौरवशाली क्षण के साक्षी बन रहे हैं। लंबे इंतजार और निरंतर प्रयासों के बाद यह ऐतिहासिक अवसर आया है।

उन्होंने बताया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार दिसंबर 2026 तक रेल लाइन को सीधी तक तथा वर्ष 2028 तक सिंगरौली तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

10 रुपए में रीवा तक का होगा सफर

यह भी बड़ी बात है कि चुरहट से रीवा एवं रीवा से चुरहट का किराया मात्र 10 रुपए है। जबकि समय जरूर ज्यादा लगेगा परंतु किराया बहुत ही कम है। जिससे आम लोगों के लिए काफी सस्ता सफर होगा इसके लिए क्षेत्रवासियों एवं सबसे अधिक रीवा जाने वाले छात्रों में काफी उत्साह भी बना हुआ है।

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा साकार हुआ वर्षों पुराना सपना



उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि आज सपनों के साकार होने का ऐतिहासिक दिन है। वर्ष 2016 में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने जिस रेल परियोजना की नींव रखी थी, वह वर्ष 2026 में साकार हो रही है। यह रेल लाइन प्रदेश की ऊर्जाधानी सिंगरौली को रीवा और सतना के सीमेंट उद्योगों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

वोट चोरी करके बनी भाजपा सरकार को जनता देगी जवाब-ज्ञान

सीधी (ब्यूरो)

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार वोट बचाओ देश बचाओ अभियान के अंतर्गत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुचवाही द्वारा ग्राम जनकपुर तथा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बरमबाबा द्वारा ग्राम पड़री में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह की विशेष उपस्थिति में जन चौपाल का आयोजन किया गया। संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने



मतदाताओं से संवाद कर वोट चोरी मतदाता सूची में गड़बड़ी और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। ज्ञान सिंह ने जन चौपाल में संवाद करते हुए कहा कि वोट की ताकत छीनने वालों को जनता करारा जवाब देगी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने आगे कहा कि भाजपा की सरकार जनादेश से नहीं बल्कि कथित वोट चोरी की राजनीति के सहारे सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा मतदाता के वोट चोरी से है चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक मतदाता के वोट की निष्पक्ष सुरक्षा सुनिश्चित करे किसी भी मतदाता को उसके अधिकार से वंचित करने का अधिकार किसी को नहीं है।

ग्राम सभा के अधिकारों में कटौती का प्रस्ताव लोकतंत्र पर चोट-रामचरण



सीधी (ब्यूरो)

आम आदमी पार्टी मध्यप्रदेश के प्रदेश सचिव राम चरण सोनी ने डॉ. मोहन यादव सरकार द्वारा ग्राम सभा के अधिकारों में बदलाव कर उन्हें पंचायत समितियों को सौंपने की प्रस्तावित योजना पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा है कि ग्राम सभा केवल एक औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि ग्रामीण लोकतंत्र की आत्मा है। गाँव के लोगों को अपने गाँव के विकास, सरकारी योजनाओं, हितग्राहियों के चयन और सार्वजनिक धन के उपयोग पर अपनी बात रखने तथा निगरानी करने का अधिकार मिलना चाहिए। राम चरण सोनी ने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल स्पष्ट करें कि आखिर ग्राम सभा के अधिकारों में बदलाव की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। यदि ग्राम सभा की अनिवार्यता तो बनी रहेगी, लेकिन उसके महत्वपूर्ण अधिकार दूसरी संस्थाओं को सौंप दिए जाएंगे, तो ग्राम सभा की भूमिका और ग्रामीणों की वास्तविक निर्णय क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सरकार को इन सवालों का जवाब प्रदेश की जनता को देना चाहिए।

एनसीएल ने साइबर अपराधों से बचाव एवं सुरक्षित डिजिटल व्यवहार पर आयोजित किया व्याख्यान सत्र

सीधी (ब्यूरो)

कोल इंडिया की सिंगरौली स्थित अनुषंगी कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) में शनिवार को सतर्कता जागरुकता अभियान 2026 के आलोक में 'बिकमिंग साइबर ब्लैक बेल्ट' शीर्षक के तहत एक वर्चुअल जागरुकता सत्र का आयोजन किया गया। एआई के युग में साइबर अपराधियों एवं साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरुकता बढ़ाने तथा सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित इस सत्र में अनीश प्रसाद, आईपीएस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस, क्राइम ब्रांच अगरतला, ने प्रतिभागियों को साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस दौरान एनसीएल सीएमडी व निदेशकगण, सीवीओ, एनसीएल, कृति महिला मंडल की अध्यक्षा, उपाध्यक्षागण सहित मुख्यालय और सभी परियोजना एवँ इकाइयों के महाप्रबंधक, विभागाध्यक्षों, कर्मचारियों तथा उनके पारिवारिक सदस्यों ने भाग लिया। व्याख्यान सत्र के शुभारंभ में सीएमडी एनसीएल, एन. फ्रैंकलिन जयकुमार ने ऐसे आयोजनों को वर्तमान साइबर परिदृश्य में बेहद प्रासंगिक बताया।

साथ ही कर्मियों के साथ साथ पारिवारिक सदस्यों को ऐसे कार्यक्रमों से जुड़कर लाभ लेने का आह्वान किया।



कंचन ज्वेलर्स डकैती कांड का अंतिम आरोपी गिरफ्तार



सीधी (ब्यूरो)

जयंत के बजरंग मार्केट स्थित कंचन ज्वेलर्स में बीते दिनों हुई सनसनीखेज डकैती के मामले में सिंगरौली पुलिस ने छठवें और अंतिम आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राहुल कुमार को जयंत पुलिस ने साइबर सेल सिंगरौली और आरपीएफ जबलपुर की मदद से जबलपुर रेलवे स्टेशन से पकड़ा। पुलिस के अनुसार आरोपी राहुल चेन्नई से लौटा था और दोबारा वहीं जाने की फिराक में था।

इस गिरफ्तारी के साथ ही 17 सितंबर को हुए सशस्त्र लूटकांड में शामिल सभी 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। आरोपी के कब्जे और निशानदेही पर 11 सोने के जेवर, चांदी की दो मूर्तियां, 4,750 रुपए नकद, एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है।

जंगल में लूट के माल का किया था बंटवारा

पुलिस के अनुसार वारदात के बाद आरोपी अनपरा पहुंचे। वहां एक चर्च के पीछे झाड़ियों में कपड़े और जूते-चप्पल बदलकर पहचान छिपाने की कोशिश की। इसके बाद रेणुकूट के जंगल क्षेत्र में लूटे गए आभूषण और नकदी आपस में बांट लिए। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल सामग्री और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं।

आरोपी अनुराग कुमार चंद्रवंशी और लकी कुमार पासवान पहले पकड़े गए थे। इनके पास से लूट के आभूषण, नकदी, मोबाइल और हथियार बरामद किए गए। एक अन्य आरोपी रोशन स्वीपर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। इसके बाद झारखंड पुलिस के सहयोग से साबिर उर्फ सोनू अंसारी और शमशाद अंसारी उर्फ छोटू को भी गिरफ्तार किया गया था। अब छठवें तथा अंतिम फरार आरोपी भी दबोच लिया गया है।

यह प्रकरण थाना विंध्यनगर में अपराध क्रमांक 461/2026 में दर्ज है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है और अन्य मामलों में उनकी संलिप्तता की जानकारी संबंधित राज्यों की पुलिस से जुटाई जा रही है। प्रकरण की विवेचना जारी है।

आदिशक्ति गरबा महोत्सव का आयोजन आज

सीधी (ब्यूरो)

सीधी में दशकों से विश्वास की परम्परा कायम रखने वाले मोहिते ज्वेल्र्स के संचालक महेश मोहिते ने चर्चा के दौरान बताया कि स्टार डांस ग्रुप द्वारा आयोजित आदिशक्ति गरबा महोत्सव सीजन-7 का आयोजन रविवार 25 अक्टूबर 2026 को शाम 6 बजे से किया जाएगा। आयोजन को लेकर महिनो पूर्व तैयारियां चल रही थीं जो कि अब मूर्त रूप ले ली हैं। आयोजकों ने नगरवासियों एवं उनके परिवारों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित किया है। श्री मोहिते ने बताया कि कार्यक्रम में सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। महोत्सव के माध्यम से मां आदिशक्ति की आराधना के साथ गरबा नृत्य और सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों ने शोसल मीडिया माध्यम से दिए आमंत्रण संदेश में कहा है कि अतिथियों एवं उनके परिवार की गरिमामयी उपस्थिति कार्यक्रम को भव्य और यादगार



बनाएगी तथा आयोजन का उत्साह बढ़ाएगी। आयोजन समिति की ओर से सुमित भारती ने चर्चा के दौरान बताया कि उक्त महोत्सव को मोहिते ज्वेलर्स द्वारा पावर्ड किया जा रहा है। वहीं सुविधा मोबाइल, स्वाति मेकओवर, कमल कंबार, कॉफी हट, जमोड़ी ऑटो डील, निखिल मोटर्स तामसर, शुभी श्रृंगार स्टोर एवं ब्राइट स्टूडियो सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों का सहयोग प्राप्त है। कार्यक्रम फैशन वर्ल्ड शोरूम एवं अबोध बाल शिक्षा निकेतन हाई स्कूल सीधी से भी जुड़ा हुआ है। आयोजकों ने सभी नगरवासियों से परिवार सहित कार्यक्रम में पहुंचकर महोत्सव की शोभा बढ़ाने की अपील की है।

भाजपा जिलाध्यक्ष ने कार्यक्रम को किया संबोधित

'लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ' अभियान पर छात्र संवाद

सीधी (ब्यूरो)

भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह ने जिले व्यापक रूप से चल रहे अभियान लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ के सिलसिले मे आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला मे देवसर विधानसभा स्थित बरगवां के सर्व हितकारी संस्था मे युवा संवाद को संबोधित किया। इस आयोजन के समय कार्यक्रम के सह संयोजक ध्रुव सिंह तथा संस्था के निदेशक डॉ सुशील पाल एवं संस्था के छात्रों समेत सैकड़ों युवा उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष ने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि इस समय देश का विपक्ष और कम्युनिस्ट दोनों लगातार लोकतंत्र मे पराजय का सामना कर रहे हैं और उनके पास आज कोई जमीन नहीं बची है वहीं दूसरी तरफ भारत पूरे विश्व मे तरक्की के झंडे गाड़ रहा है । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों सहित 14 विपक्षी पार्टियों को अपने अस्तित्व पर खतरा मंडराता दिख रहा है और उनके पास जब कोई ठोस मुद्दे नहीं बचे तो वो झूठ और मिथ्या तथ्यों का सहारा लेकर अनर्गल आरोप लगाने लगे हैं और भारत विरोधी ताकतों से पोषित होकर देश में आंदोलनों का आड़ लेकर अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस कम्युनिस्ट और काकरोच खुलेआम देश मे नेपाल और बांग्लादेश जैसे हिंसक आंदोलनों की धमकी पर उतर आए हैं और हमें उनकी इस घटिया सोच को नकारते हुए वास्तविकता का आइना दिखाना है और अपने देश मे स्थिरता कायम रखते हुए सच्चे लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करना है। हमारे देश की युवा पीढ़ी राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है और विदेशी टुकड़ों पर पलने वाले राष्ट्र विरोधी तंत्रों को जरा भी पनपने नहीं देगी। इस आयोजन मे क्षात्रों ने अपना समर्थन देश की मजबूत सरकार और राष्ट्रवादी सिद्धांतों पर प्रकट किया तथा देश मे चंद मुट्ठी भर भटके युवाओं को आइना दिखाने का काम किया।



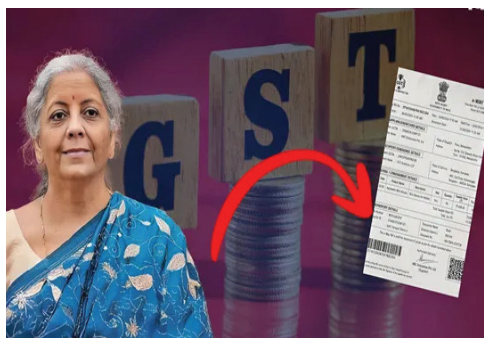
संबल योजना में अनियमितता पर बड़ी कार्रवाई

पंचायत समन्वयक निलंबित; गुलाब जायसवाल पर एफआईआर के निर्देश

सीधी (ब्यूरो)

मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत कथित अनियमितताओं के मामले में जिला पंचायत सिंगरौली ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संघ प्रिय, आईएएस द्वारा 23 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, जनपद पंचायत चितरंगी में पदस्थ पंचायत समन्वयक अधिकारी रमई कोल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, संबल योजना में कथित धोखाधड़ी, कूटरचना और अवैध रूप से राशि वसूलने के मामले में ग्राम खटाई निवासी गुलाब जायसवाल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिला पंचायत द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, ग्राम पंचायत खटाई की सरपंच श्रीमती हीरामन देवी साहू की 30 दिसंबर 2025 को प्रस्तुत शिकायत के आधार पर संबल योजना के दो प्रकरणों की सूक्ष्म जांच कराई गई थी। जांच में क्षेत्रीय पंचायत समन्वयक अधिकारी रमई कोल पर कथित रूप से अपात्र हितग्राहियों के मामलों में नियमों के विपरीत स्वीकृति योग्य अनुशंसा करने और अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप सामने आए। इसी प्रकरण से जुड़े एक अन्य आदेश में जिला पंचायत ने ग्राम खटाई निवासी गुलाब जायसवाल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार, ज्ञानेन्द्र प्रसाद केवट ने 22 अक्टूबर 2026 को दर्ज अपने कथन में आरोप लगाया कि पत्नी की मृत्यु के बाद संबल योजना के तहत सहायता राशि दिलाने का आश्वासन देकर गुलाब जायसवाल ने उनके दस्तावेज अपने पास रख लिए और दो लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत कराने के बदले एक लाख रुपये की मांग की।

GST रिटर्न फॉर्म पर वित्त मंत्रालय कर रहा बड़ा बदलाव, 1 नवंबर व्यापारियों के लिए है खास! मंत्रालय को भेजें सुझाव



नई दिल्ली (एजेंसी)। GST काउंसिल की 57वीं बैठक के बाद कई अहम बदलाव देखने को मिले, जिसमें जीएसटी रिटर्न में जरूरी चेंजेस देखने को मिले हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्त मंत्रालय मासिक 'जीएसटी रिटर्न फॉर्म' में प्रस्तावित बदलावों पर 1 नवंबर से कारोबारियों की राय मांगेगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के GST पॉलिसी डिविजन के कमिशनर गौरव सिंह ने कहा कि विभाग जीएसटी ऑडिट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की दिशा में भी काम करेगा। इससे टैक्स पेयर्स के लिए प्रक्रिया आसान होने की संभावना जताई जा रही है।

8 अक्टूबर को केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्रियों वाली त्नस्ज्ञ काउंसिल की 57वीं बैठक में जीएसटी रिटर्न (टैक्स वापसी) में देनदारियों और इनपुट टैक्स क्रेडिट में संशोधन के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था को मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य विसंगतियों को कम करना और नोटिस या सूचना भेजने की जरूरत में कमी लाना है। काउंसिल ने त्नस्ज्ञ फॉर्म जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-1 और ढ्ढस्रस्त्र में सुधारों को मंजूरी दी थी, ताकि इन फॉर्म में दी गई जानकारी का मासिक कर भुगतान फॉर्म जीएसटीआर-3क्र में दी गई जानकारी से बेहतर मिलान किया जा सके।

GST पॉलिसी डिविजन के कमिशनर गौरव सिंह ने कहा कि संशोधित त्नस्ज्ञ रिटर्न फॉर्म 1 नवंबर को 'स्वत्नश्1' प्लेटफॉर्म पर पब्लिक ओपीनियन के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। इन पर 30 नवंबर तक सुझाव दिए जा सकेंगे। संशोधित जीएसटी रिटर्न फॉर्म 1 अप्रैल, 2027 से लागू होगा। 8 अक्टूबर को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए फैसलों से संबंधित नॉटिफिकेशन और सर्कुलर की विधि विभाग ने जांच कर ली है। इन्हें शुक्रवार को सार्वजनिक किया जाएगा।

सिंह ने साथ ही ये भी कहा कि ITC सीरिज की अखंडता से जुड़ी समस्याएं दूर होने पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में आगे के सुधारों को गति मिलेगी। उन्होंने कहा, ऑडिट के संबंध में हमें समीक्षा करनी होगी।

त्नस्ज्ञ नीति प्रभाग के आयुक्त ने कहा कि प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि टैक्सपेयर्स को परेशानी का सामना न करना पड़े। फिलहाल, एक से अधिक राज्यों में कारोबार करने वाली कंपनियों को उन राज्यों के जीएसटी अधिकारियों द्वारा कई बार ऑडिट का सामना करना पड़ता है।

दीपावली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा, 30 अक्टूबर को आएगी 24वीं किस्त; आधिकारिक तारीख घोषित



नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खबर है। यह किस्त कब आएगी इसकी आधिकारिक तौर पर तारीख घोषित हो चुकी है। एक तरह से दीपावली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा मिला है। 24वीं किस्त जारी होने की आधिकारिक तारीख 30 अक्टूबर घोषित की गई है। यानी 30 अक्टूबर को किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये आएंगे।

किसानों के खाते में 24वीं किस्त का पैसा दीपावली से पहले आएगा। जागरण बिजनेस ने अपनी पिछली रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की थी कि पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त दीपावली से पहले भेजी जा सकती है। और अब कृषि मंत्रालय ने भी आधिकारिक तौर पर 24वीं किस्त जारी होने की तारीख घोषित करके हमारी खबर पर मुहर लगा दी है।

पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त की आधिकारिक तारीख की घोषणा पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट, और सोशल मीडिया पर दी गई। किसान योजना के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भी इसकी जानकारी दी गी।

पीएम किसान योजना के आधिकारिक एक्स हैंडल के पोस्ट में लिखा गया- तारीख नोट कर लें! PM-KISAN की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी, जिससे हमारे अन्नदाताओं को लगातार आर्थिक सहायता मिलेगी और वे सशक्त होंगे।

30 अक्टूबर को पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी होगी। इस दिन पात्र किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपये आएंगे। यह किस्त दीपावली से पहले जारी की जा रही है। ऐसे में किसानों के लिए त्योहार से पहले मिलने वाली यह किस्त किसी तोहफे से कम नहीं।

हालांकि, जिन किसानों की द्द-चङ्घष्ट नहीं हुई है, उनका पैसा रुक सकता है। अगर आप भी एक पात्र किसान हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी किस्त आएगी या नहीं तो आपको अपना ताजा स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए।

इसके लिए आपको किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट द्धह्लह्लश्चह्य-//श्चद्वद्मद्वह्यड्डठ्ठ.द्दश1.द्व ठ्ठ/ पर जाना होगा और फॉर्मर सेक्शन में जाकर लॉगिन करना होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ह्वञ्जक्र आएगी। ओटीपी दर्ज करें।

इसके बाद नया पेज ओपन होगा, जहां किस्त से जुड़ी डिटेल होगी। और अगर आपकी ई-केवाइसी नहीं हुई होगी तो भी आपको यहीं पता लग जाएगा।

दिसंबर में आरबीआई दे सकता है एक और झटका, लगातार दूसरी बार बढ़ा सकता है रेपो रेट



नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हालिया अक्टूबर मिनट्स यानी मीटिंग का ब्यौरा सामने आया। जिसके बाद अर्थशास्त्रियों ने अनुमान जताया है कि दिसंबर में लगातार दूसरी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी हो सकती है।

बैठक के मिनट्स से साफ है कि आरबीआई का रुख अब पहले से काफी ज्यादा हॉकिश यानी सख्त हो गया है। बढ़ती महंगाई और रुपए पर पड़ रहे भारी दबाव को देखते हुए दिसंबर में रेपो रेट 50 बेसिस प्वाइंट तक बढ़ाया जा सकता है।

देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की ताजा रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर की नीतिगत बैठक में 50 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की पूरी गुंजाइश है।

यह इजाफा दो तरीकों से हो सकता है- या तो सीधे रेपो रेट में 50 ङ्कश्चह्य की बढ़ोतरी की जाए, या फिर इसे बांटकर 25 बेसिस प्वाइंट रेपो रेट बढ़ाया जाए और बाकी 25 बेसिस प्वाइंट के जरिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर को चौड़ा किया जाए।

एसबीआई के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉ. सौम्य कांति घोष ने स्पष्ट किया है कि, महंगाई का दायरा लगातार बढ़ रहा है और रुपए की कमजोरी भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में आरबीआई को बेहद संतुलित कदम उठाने होंगे। हालांकि नवंबर तक महंगाई दर 6.5 प्रतिशत से नीचे आ सकती है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए आरबीआई को सतर्क रहना होगा।

कैलिब्रेटेड टाइटनिंग और महंगाई का डर - डीबीएस बैंक की सीनियर इकोनॉमिस्ट राधिका राव ने बताया कि अक्टूबर की बैठक में रेपो रेट 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाया गया था और नीतिगत रुख को बदलकर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग (नपी-तुली सख्ती) कर दिया गया था।

एमपीसी सदस्यों का साफ मानना है कि मजबूत आर्थिक वृद्धि और बढ़ती महंगाई, दरें बढ़ाने की मुख्य वजह हैं। बैठक में कुछ सदस्य पहले से ही सख्त कदम उठाने के पक्ष में थे, जबकि कुछ क्रमिक बढ़ोतरी चाहते थे। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी संकेत दिया है कि महंगाई अब ज्यादा व्यापक रूप ले रही है। राधिका राव के मुताबिक, अगर चौथी तिमाही में महंगाई 6त्न के आसपास रहती है, तो दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ना लगभग तय है।

कच्चा तेल बढ़ा सकता है टेंशन- विदेशी मुद्रा बाजार में किए गए नियामकीय सुधारों और देश के सबसे बड़े इक्विटी आईपीओ में आए विदेशी निवेश के चलते रुपए को काफी सपोर्ट मिला है। इसी का नतीजा है कि इस महीने डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 1.5त्न मजबूत हुआ है।

हालांकि, अर्थशास्त्रियों की चिंता इस बात को लेकर है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (ष्टह्लह्वस्रद्व ह्लद्बद्य ब्रह्लद्बष्ट्र) की बढ़ती कीमतें और ग्लोबल रिस्क आने वाले समय में बॉन्ड बाजार पर भारी दबाव बनाए रख सकते हैं, जिससे चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं।

गलत संबंध के आरोप स्वीकार कर न्यूजीलैंड के आर्मी चीफ ने दिया इस्तीफा, कहा- अतीत की गलतियों की जिम्मेदारी लेता हूं



नई दिल्ली (एजेंसी)। न्यूजीलैंड के आर्मी चीफ टोनी डेविस ने एक राने अनुचित संबंध और समय पर उसका खुलासा न करने की बात स्वीकार करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रक्षा मंत्री पॉल गोल्डस्मिथ को भेजे गए इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि उनका यह आचरण सेना के मूल्यों के खिलाफ था और वह अपने अतीत के गलत फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं।

डेविस ने कहा, यह इस्तीफा निजी कारणों से है, और मेरे द्वारा अतीत में की गई गलतियों का परिणाम है, जिसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ये गलतियां रक्षा बल के मूल्यों के विपरीत थीं।

डेविस ने कहा कि यह मामला उनके यूनिट कमांड के पद पर रहते हुए मेरे द्वारा बनाए गए एक अनुचित संबंध के इर्द-गिर्द घूमते थे, और मुझे इस बात का अफसोस है कि जब मेरे पास ऐसा करने का अवसर था तब मैंने इसका खुलासा नहीं किया।

रक्षा मंत्री ने उनके इस्तीफे को मंजूरी के लिए गवर्नर-जनरल के पास भेज दिया है, जबकि उप प्रमुख मैट विलियम्स को फिलहाल रक्षा बल का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है।

क्या बोले रक्षा मंत्री-न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्री पॉल गोल्डस्मिथ ने कहा कि वह इस बात से सहमत हैं कि डेविस का पद अब कायम रखने योग्य नहीं है। उन्होंने सत्यनिष्ठा से जुड़े उन मामलों पर चिंता जताई जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था।

गोल्डस्मिथ ने कहा, उनके इस फैसले के पीछे के कारण सत्यनिष्ठा से जुड़े मामले हैं. जिनका उन्होंने पहले खुलासा नहीं किया था। उन्होंने आगे कहा, मैं गवर्नर-जनरल को यह सिफारिश करूंगा कि वह डेविस का इस्तीफा स्वीकार कर लें।

कौन संभालेगा कार्यभार- न्यूजीलैंड रक्षा बल ने एक बयान में कहा कि डेविस ने रक्षा मंत्री पॉल गोल्डस्मिथ को अपने पद से इस्तीफा देने के फैसले की जानकारी दी। सेना के बयान के अनुसार, रक्षा बल के उप प्रमुख मैट विलियम्स कार्यवाहक प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे।

बताते चले कि डेविस 1984 में न्यूजीलैंड की सेना में शामिल हुए और 2024 में उन्हें शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया।

पेरिस में अंधाधुंध फायरिंग में एक की मौत और कई घायल, हमलावर दबोचा गया



नई दिल्ली (एजेंसी)। पेरिस के उपनगर में गोलीबारी हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने घटना की सूचना दी।

फ्रांसीसी ब्रॉडकास्टर ने दी जानकारी- फ्रांसीसी ब्रॉडकास्टर ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शुक्रवार को पेरिस के पास एक उपनगर की सड़क पर हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन लोग घायल हुए हैं।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया- गोलीबारी के आरोपी को यवेलिन्स विभाग के कॉइनिएरेस इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक हमले के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।

भारत को मिली बड़ी कामयाबी! ऑयल इंडिया ने कृष्णा-गोदावरी बेसिन में खोजा प्राकृतिक गैस का भंडार



नई दिल्ली (एजेंसी)। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की मची किल्लत के बीच भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। भारत की सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड को कृष्णा-गोदावरी बेसिन के उथले समुद्री क्षेत्र में एक ब्लॉक में प्राकृतिक गैस मिली है। कंपनी ने हाल में खोजे गए छोटे क्षेत्रों (डीएसएफ) की बोली प्रक्रिया के दौरान यह ब्लॉक हासिल किया था।

कंपनी ने शुक्रवार को बयान में कहा कि यह गैस भारत के पूर्वी तट के पास कृष्णा-गोदावरी बेसिन में मत्स्यपुरी 'फॉर्मेशन' में मिली, जिसका पहले कभी मूल्यांकन नहीं किया गया था। इस दौरान परीक्षण में अधिकतम 2,00,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन (एससीएमडी) गैस प्रवाह दर्ज किया गया।

ओआईएल ने कहा कि यह खोज केजी-डीएसएफ/जीएसकेडब्ल्यू/2018 नाम के उथले समुद्री अपतटीय ब्लॉक में गोदावरी-1 आकलन कुएं में हुई। इसमें 16 अक्टूबर, 2026 को 2,024-2,027 मीटर की गहराई पर हाइड्रोकार्बन युक्त क्षेत्र का परीक्षण शुरू किया गया था।

कंपनी ने कहा कि इस कुएं से करीब 1,00,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से गैस निकल रही है। निरंतर परीक्षण के दौरान अधिकतम 2,00,000 एससीएमडी की दर दर्ज की गई। कंपनी ने करीब 170 बैरल प्रतिदिन 'कंडेनसेट' उत्पादन की भी जानकारी दी।

'कंडेनसेट' किसी गैस या वाष्प के ठंडा होने या संघनन के बाद बनने वाला तरल पदार्थ है। ओआईएल ने कहा कि अधिक गहराई वाले क्षेत्र का परीक्षण करने की तैयारियां जारी हैं।

हालांकि, कंपनी ने इस खोज में मौजूद संभावित संसाधनों की मात्रा का कोई आकलन नहीं दिया। यह खोज ऐसे समय में घरेलू गैस का एक अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध करा सकती है, जब भारत अपनी प्राकृतिक गैस की जरूरतों के एक बड़े हिस्से को पूरा करने के लिए अब भी आयात पर निर्भर है।

सरकार ने भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी मौजूदा करीब छह प्रतिशत से बढ़ाकर 2030 तक 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में घरेलू संसाधनों का विकास उसकी ऊर्जा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

ताइवान में तूफान चांपी का कहर- 20 शहरों में शटडाउन, स्कूल-ऑफिस बंद; 1000 उड़ानें रद



नई दिल्ली (एजेंसी)। ताइवान में तूफान चांपी के आने से पहले काफी सतर्कता बरती जा रही है। 170 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना के मद्देनजर स्कूल और ऑफिसों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। सैंकड़ों उड़ानें रद कर दी गई हैं।

तूफान ताइवान के काफी करीब पहुंच चुका है। इसके लिए प्रशासन पहले से अपनी तैयारी कर रहा है। आंधी और तेज बारिश के साथ खतरनाक मौसम की वजह से प्रशासन एहतियातन ये कदम उठा रहा है।

स्थानीय प्रशासन के अनुसार स्कूल और ऑफिस ग्रेटर ताइपे, कीलुंग और ताओयुआन सहित कई इलाकों में शुक्रवार को बंद करने की घोषणा की गई है। वहीं, दक्षिणी ताइवान में युनलिन, चियायी, ताइनान, काओशुंग और पिंगतुंग में भी बंद की तैयारी है। पूर्वी ताइवान के साथ बाहरी द्वीप जिनमें यिलान, हुआलिएन, पेंघु और लिएनचियांग शामिल हैं यहां पर भी बंद की घोषणा है। एहतियातन यहां पर कामकाज बंद कर दिया गया है।

ताइवान की केंद्रीय मौसम प्रशासन ने गुरुवार को तूफान चांपी के करीब पहुंचने पर एक चेतावनी जारी की। जमीनी चेतावनी 22 अक्टूबर की सुबह जारी की गई है। इसमें लोगों से प्रशासन द्वारा बताए गए नियमों को फॉलो करने के लिए कहा गया है।

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार तूफान शुक्रवार की सुबह से शाम के बीच ताइवान पहुंच सकता है। अनुमान है कि शनिवार की शाम तक इस तूफान का असर दिखेगा। इसके बाद इसका असर

सिर्फ 10000 से शुरू करें मोमबत्ती बनाने का कारोबार, दीवाली पर होगी मोटी कमाई



नई दिल्ली (एजेंसी)। दीवाली का त्योहार नजदीक आते ही बाजार में रंग-बिरंगी सजावटी चीजों की मांग बढ़ने लगती है। ऐसे में अगर आप कम निवेश में अपना कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं, तो मोमबत्ती बनाने का बिजनेस एक विकल्प हो सकता है। खास बात यह है कि इसे घर के छोटे से कमरे से भी शुरू किया जा सकता है। शुरुआती स्तर पर करीब 10,000 से 15,000 के निवेश के साथ इस काम की शुरुआत की जा सकती है। हालांकि, कमाई इस बात पर निर्भर करेगी कि आपके प्रोडक्ट कितने बिकते हैं और उन्हें तैयार करने में कितनी लागत आती है।

दीवाली पर क्यों बढ़ती है मोमबत्ती की मांग- दीवाली पर घरों, दुकानों और ऑफिसों को सजाने के लिए लोग अलग-अलग तरह की मोमबत्तियां खरीदते हैं। बाजार में सामान्य मोमबत्तियों के अलावा रंगीन, डिजाइनर और खुशबूदार कैंडल भी पसंद की जाती है। इनकी बिक्री सिर्फ दीवाली तक सीमित नहीं रहती। जन्मदिन की पार्टियों, शादी, धार्मिक कार्यक्रमों और गिफ्टिंग के लिए भी इनकी इस्तेमाल होता है।

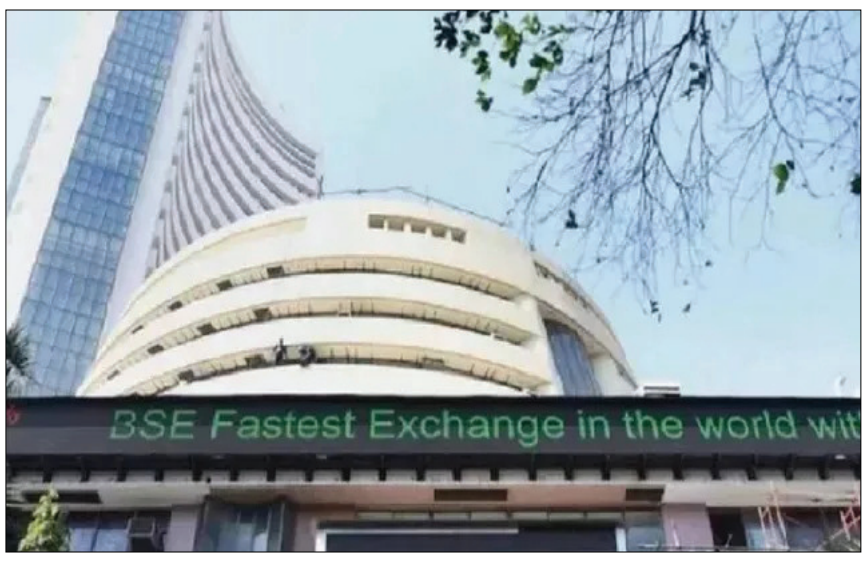
ऐसे में छोटो कारोबारी त्योहार के दौरान स्थानीय बाजारों में अपनी मोमबत्तियां बेच सकते हैं। अगर प्रोडक्ट की डिजाइन और पैकेजिंग अच्छी हो, चो उन्हें गिफ्टिंग के लिए तैयार भी किया जा सकता है।

10000 में कैसे शुरू होगा बिजनेस- मोमबत्ती बनाने के बिजनेस की खासियत यह है कि शुरुआत में महंगी मशीन खरीदना जरूरी नहीं है। छोटे स्तर पर सांचों की मदद से हाथ से मोमबत्तियां की जा सकती हैं।

शुरुआत के लिए इन चीजों की जरूरत होगी-

* मोम- मोमबत्तियां बनाने के लिए कच्चा माल।
* बत्ती और धागा- मोमबत्ती में इस्तेमाल होने वाली बत्ती।
* सांचे- अलग-अलग आकार और डिजाइन की मोमबत्तियां बनाने के लिए।
* रंग और खुशबू- सजावटी और सुगंधित कैंडल तैयार करने के लिए।
* पैकिंग का सामान- तैयार प्रोडक्ट को सुरक्षित और आकर्षक तरीके से बेचने के लिए।

शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी, सेंसेक्स 125 अंक टूटा; निफ्टी 22600 पर बंद



नई दिल्ली (एजेंसी)। सप्ताह के आखिरी ट्रेडिंग दिन में बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। शुक्रवार को भारतीय रुपया लगातार दूसरे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ। यह 12 पैसे गिरकर 94.94 प्रति डॉलर पर आ गया, जबकि पिछले सत्र में यह 94.82 पर बंद हुआ था। कारोबार के अंत में, सेंसेक्स 125.56 अंक या 0.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 73,123.83 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 87.65 अंक या 0.39 प्रतिशत गिरकर 22,600 पर आ गया।

किन शेयरों में दिखी सबसे ज्यादा गिरावट- निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज करने वालों में श्रीराम फाइनेंस, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, अदाणी एंटरप्राइजेज, टाटा स्टील और जियो फाइनेंशियल शामिल थे। इसके अलावा, अपोलो हॉस्पिटल्स, इंफोसिस, टीसीएस और मारुति सुजुकी में भी गिरावट देखने को मिली।

सभी सेक्टोरल सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स में 3 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि रियल्टी, एनर्जी, मेटल और पीएसयू बैंक सूचकांकों में 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।

निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 2.5 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स 2.9 प्रतिशत नीचे आ गया।

क्या बोले एक्सपर्ट-जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड, विनोद नायर ने कहा- आज के बाजार में मुख्य चिंता निफ्टी की तुलना में मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों में आई बहुत बड़ी गिरावट है। वैल्युएशन को लेकर चिंताएं, लीवरेज्ड पोजीशन (उधार लेकर बनाई गई पोजीशन) को कम करना, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और वैश्विक स्तर से मिल रहे कमजोर संकेतों ने पूरे बाजार पर दबाव बढ़ा दिया है। इंडिया VIX में उछाल यह भी बताता है कि निकट भविष्य में बाजार में उतार-चढ़ाव (वोलैटिलिटी) बना रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं, जबकि ढ्ढ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से जुड़े वैश्विक इक्विटी बिकवाली के दौर ने निवेशकों के जोखिम लेने की क्षमता को प्रभावित किया है। आगे चलकर, महंगाई के रुझान और महंगाई तथा विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रमुख केंद्रीय बैंकों के कदम बाजार की दिशा तय करने में अहम होंगे। ऐसे माहौल में, हमें उम्मीद है कि स्टॉक और सेक्टर-विशेष के अवसर हावी रहेंगे, जहां कंपनियों की कमाई की स्पष्टता और वैल्युएशन का सही स्तर, निवेश के फैसले लेने में मुख्य आधार बनेंगे।

रियर व्यू मिरर में देखकर भविष्य की ओर गाड़ी नहीं चलाई जा सकती



नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की मांग की है। भारत ने चेतावनी दी है कि 80 साल पुराना इसका ढांचा दुनिया के कुछ सबसे गंभीर संघर्षों को सुलझाने में संघर्ष कर रहा है।

भारत का कहना है कि सुरक्षा परिषद का स्वरूप आज की वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप होना चाहिए। भारत का तर्क है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना इसका ढांचा अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

भारत ने क्या कहा- न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्वथानेनी हरीश ने गुरुवार को कहा कि दूसरे विश्व युद्ध से मिली सत्ता सुरक्षा परिषद में उचित प्रतिनिधित्व की कमी की भरपाई नहीं कर सकती।

पार्वथानेनी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुरक्षा परिषद के विस्तार और उसमें समान प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर बोलते हुए कहा, इसके नतीजे पहले ही सामने आ रहे हैं। 80 साल बीत जाने के बाद भी यह संगठन परिषद के सामने मौजूद कुछ सबसे गंभीर संघर्षों में शांति और सुलह कराने में संघर्ष कर रहा है।

उन्होंने आगे कहा, आठ दशक पहले मिली जीत से मिलने वाला अधिकार आज की ऐसी सुरक्षा परिषद की वैधता की कमी को पूरा नहीं कर सकता, जो दुनिया का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। भारतीय दूत ने तर्क दिया कि 1945 में जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र (ह्र) की स्थापना हुई थी, उसे वैश्विक शासन के लिए एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निकुंज धाम गौशाला में किया गोमाता का पूजन



भोपाल ब्यूरो। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धार के सरदारपुर की निकुंज धाम गौशाला में गोमाता का पूजन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गौशाला के संचालन, व्यवस्थाओं तथा गौवंश के संरक्षण एवं देखभाल के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

पोलियो रोधी खुराक से कोई बच्चा वंचित न रहे : डॉ. यादव

भोपाल ब्यूरो। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विश्व पोलियो दिवस (24 अक्टूबर) हम सबको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि देश का एक भी बच्चा पोलियो रोधी खुराक पाने से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 'एक्स' पर कहा कि सभी माता-पिता और अभिभावक अपने बच्चों को समय पर 'दो बूंद जिंदगी की' अवश्य पिलाएं और उनके स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनभागीदारी और जागरूकता से ही हम पोलियो मुक्त भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं।

सीएम ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के स्थापना दिवस की दीं शुभकामनाएं

भोपाल ब्यूरो। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के स्थापना दिवस पर सभी वीर जवानों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। डॉ. यादव ने 'एक्स' पर कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा, दुर्गम परिस्थितियों में कर्तव्यपालन और राष्ट्र की सेवा के प्रति भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवानों का साहस, समर्पण एवं अनुशासन हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्र की सुरक्षा में सक्रिय योगदान के लिए पूरे बल का अभिनंदन किया है।

मुख्यमंत्री आज शहडोल में करेंगे तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि का वितरण

भोपाल ब्यूरो। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार 25 अक्टूबर को शहडोल से जिला शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी और सतना जिले के तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2024 के 9 लाख 77 हजार 696 पात्र तेंदूपत्ता संग्राहकों को 22 करोड़ 89 लाख 9 हजार 461 रुपये बोनस राशि का वितरण करेंगे। कार्यक्रम में 15 हजार से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहक शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शहडोल जिले के 461.73 करोड़ रुपये के 134 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन करेंगे। इनमें 379 करोड़ 45 लाख रुपये के 89 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और 82 करोड़ 28 लाख रुपये के 45 विकास कार्यों का लोकार्पण होगा।

विंध्य से बुंदेलखंड को जोड़ने वाली पहली ट्रेन दौड़ी

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा- साकार हुआ वर्षों पुराना सपना

भोपाल (ब्यूरो)





भोपाल। सीधी जिले के रामपुर नैकिन-चुरहट क्षेत्र में पहली बार रेल सेवा शुरू होने के अवसर पर उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। देवेंद्रनगर-चुरहट ट्रेन सेवा के शुभारंभ के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, सीधी सांसद डॉ. राजेश मिश्रा, चुरहट के पूर्व विधायक शरदेंदु तिवारी, देव कुमार सिंह चौहान ने आम नागरिकों के साथ चुरहट से गोविंदगढ़ तक ट्रेन में यात्रा की। जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्रवासियों के साथ रेल सेवा शुरू होने की खुशी साझा की।

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि आज सपनों के साकार होने का ऐतिहासिक दिन है। वर्ष 2016 में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने जिस रेल परियोजना की नींव रखी थी, वह वर्ष 2026 में साकार हो रही है। यह रेल लाइन प्रदेश की ऊर्जाधानी सिंगरौली को रीवा और सतना के सीमेंट उद्योगों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए औद्योगिक क्रांति, पर्यटन क्रांति और कृषि क्रांति आवश्यक हैं, जिनकी आधारशिला मजबूत अधोसंरचना होती है। विंध्य क्षेत्र में रेल, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार से विकास की नई संभावनाएं निर्मित हो रही हैं। रीवा-सीधी-सिंगरौली रेल लाइन के साथ रीवा-सीधी फोरलेन और सीधी-सिंगरौली फोरलेन सड़क परियोजनाओं पर भी कार्य प्रगतिरत है। रीवा हवाई अड्डे के लोकार्पण के एक वर्ष के भीतर ही पांच स्थानों के लिए हवाई सेवाएं संचालित होने लगी हैं, 50 हजार से अधिक लोग इन सेवाओं का लाभ ले चुके हैं।

विद्यार्थियों और स्थानीय नागरिकों में उत्साह : नई रेल सेवा शुरू होने से विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और आम नागरिकों को आवागमन का अतिरिक्त विकल्प मिला है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से जुड़े केंद्रों तक पहुंचना अधिक सुविधाजनक होने की उम्मीद है। वहीं, नौकरी और व्यवसाय के सिलसिले में यात्रा करने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। स्थानीय नागरिकों में इस बात को लेकर खुशी रही कि अब क्षेत्र को रेल नेटवर्क के माध्यम से दूसरे स्थानों से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी रहे उपस्थित : चुरहट में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह, पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह, चुरहट के पूर्व विधायक शरदेंदु तिवारी, देव कुमार सिंह चौहान सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। इस अवसर पर कलेक्टर विकास मिश्रा, पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौम्या आनंद सहित विभिन्न विभागों के प्रशासनिक अधिकारी एवं रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। सीधी जिले के रामपुर नैकिन-चुरहट क्षेत्र का पहली बार रेल सेवा से जुड़ना स्थानीय जनजीवन, आवागमन और आर्थिक गतिविधियों के लिए नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा।

सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा- जिले में लिखी जा रही विकास की गाथा

सीधी सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा कि आज जिले में विकास की गाथा लिखी जा रही है और हम सभी इस गौरवशाली क्षण के साक्षी बन रहे हैं। लंबे इंतजार और निरंतर प्रयासों के बाद यह ऐतिहासिक अवसर आया है। दिसंबर 2026 तक रेल लाइन को सीधी तक तथा वर्ष 2028 तक सिंगरौली तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। सांसद ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पूर्व सांसदों के प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया।

रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा- दशकों पुरानी परिकल्पना हो रही साकार : रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि जिस ट्रेन सेवा की परिकल्पना वर्ष 1956 में की गई थी, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गति मिली है। इससे सतना-देवेंद्रनगर और रीवा-चुरहट रेलखंडों के विकास से विंध्य क्षेत्र को औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

भारत मंडपम में महका बालाघाट का चिन्नौर चावल, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मिला भव्य मंच

भोपाल (ब्यूरो)



भोपाल। देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित भारत मंडपम में आयोजित तीन दिवसीय 'भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2026' (BIRC-2026) में मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के गौरव, जी.आई. टैग प्राप्त 'बालाघाट चिन्नौर' चावल ने अपनी विशेष पहचान दर्ज कराई है।

'एक जिला-एक उत्पाद' के तहत चयनित इस सुगंधित चावल का सम्मेलन में भव्य प्रदर्शन किया जा रहा है। सम्मेलन में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड) भोपाल एवं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के संयुक्त तत्वावधान में चिन्नौर चावल के प्रचार-प्रसार के लिए एक विशेष स्टॉल लगाया गया है। इस वैश्विक आयोजन में बालाघाट जिले का प्रतिनिधित्व लालबर्रा चिन्नौर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कर रही है। एफपीओ के अध्यक्ष ईशुपाल चौहान एवं संचालक सदस्य राधेलाल पटले ने चावल निर्यातकों, व्यापारियों और प्रतिनिधियों को चिन्नौर चावल के महत्व से अवगत कराया।

उप मुख्यमंत्री ने तीन दिवसीय रीवा हाट का किया शुभारंभ

महिला सशक्तिकरण से टॉप-5 शहरों में शुमार होगा रीवा : शुक्ल

भोपाल (ब्यूरो)



भोपाल। रीवा की महिला उद्यमियों को एक बड़ा मंच प्रदान करने और उनके हुनर को नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में तीन दिवसीय रीवा हाट के तीसरे सीजन का गत दिवस उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शुभारंभ किया। इस आयोजन को आकर्षक बनाने के लिए विशेष फूड जोन के साथ-साथ ओपन स्टेज भी तैयार किया गया है, जहां आगंतुक और प्रतिभागी बढ़-चढ़कर अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मेले में रीवा के अलावा भोपाल, इंदौर, आगरा और प्रयागराज सहित अन्य महानगरों से आईं महिला उद्यमियों द्वारा स्टॉल लगाकर अपनी कला व स्वदेशी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने मेले में विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन भी किया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा के नागरिक और विशेषकर हमारी मातृशक्ति कितनी सजग हैं और ओनरशिप ले रही हैं, यह रीवा हाट बाजार इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। महिलाओं को सही प्लेटफॉर्म, विजिबिलिटी और मार्केट उपलब्ध कराया जाए ताकि उनका हौसला और व्यापार दोनों बढ़ सकें। महिलाओं द्वारा घर में तैयार किए जा रहे शानदार प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए इस तरह के आयोजन बेहतरीन मंच साबित हो रहे हैं। रीवा में भौतिक विकास तेज़ी से हो रहा है और आने वाले दिनों में यह गति और भी तेज होगी। आने वाले दिनों में रीवा देश के सबसे विकसित शहरों के टॉप-5 शहरों में शामिल होगा। रीवा में बाईपास निर्माण का दूसरा वर्जन शुरू होने जा रहा है। आने वाले दिनों में रीवा मध्य प्रदेश का ऐसा पहला संभागीय मुख्यालय होगा, जिसका फोर-लेन और एट-लेन रिंग रोड सबसे पहले तैयार होने वाला है। वर्तमान में 3 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी पहुंच रहा है, जो अगले 1 से 2 वर्षों में बढ़कर 6 लाख से 9 लाख एकड़ होने वाला है। इससे क्षेत्र में अभूतपूर्व समृद्धि आएगी, किसानों के पास पैसा आएगा, बाजार में खरीद-बिक्री बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

केन्द्रीय मंत्री ने बहनों-बेटियों को स्वरोजगार ऋण, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए

जब तक जीयेंगे, लोगों की जिंदगी बदलने के लिए जीयेंगे : चौहान

भोपाल (ब्यूरो)

भोपाल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को भोपाल स्थित सेज यूनिवर्सिटी में आयोजित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ब्यूटीशियन और सिलाई का प्रशिक्षण पूरा कर चुकी महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए और उन्हें स्वरोजगार शुरू करने के लिए ऋण भी प्रदान किए। महिलाओं को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि बहन-बेटियों को सीधे रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य और प्रसन्नता हुई कि कुछ बेटियों ने 35 दिनों का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अपना काम भी शुरू कर दिया है। यह इस बात का प्रमाण है कि सही प्रशिक्षण, अवसर और सहयोग मिलने पर महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकती हैं।

230 बहनों को मिली ट्रैनिंग, 80 के लोन सेंक्शन : केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, हमारा लक्ष्य हर घर में खुशी के दीप जलाना, हर हाथ को काम देना और लोगों को आजीविका की अलग-अलग गतिविधियों से



जोड़ना है। महिलाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में सक्षम बनाना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ब्यूटीशियन और सिलाई प्रशिक्षण का यह पहला बैच था, जिसमें विदिशा संसदीय क्षेत्र के चारों जिले विदिशा, सीहोर, देवास और रायसेन की कुल 230 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि, प्रशिक्षण पूरा करने वाली 80 बहन-बेटियों के लोन सेंक्शन कर दिए गए हैं, ताकि वह अपना काम शुरू कर सकें।

बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने की पहल : केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक महत्वपूर्ण पहल की योजना साझा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य के लिए एक उपयोगी पहल है, लेकिन कई परिवारों में जानकारी के अभाव या आर्थिक परिस्थितियों के कारण इसमें खाते नहीं खुल पा रहे हैं और नियमित रूप से राशि जमा नहीं हो पा रही है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 हजार बेटियों का अनुमान है। हमारा विचार है कि इन बेटियों के खातों में विभिन्न सहयोग से पहली किस्त के रूप में 1,000 रु. जमा कराए जाएंगे ताकि परिवारों को योजना से जुड़ने की शुरुआत मिल सके।

हर बेटी को मिले सम्मान की जिंदगी : केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा प्रयास है कि कोई बेरोजगार न रहे, हर व्यक्ति के हाथ में हुनर हो और हर व्यक्ति के पास रोजगार का अवसर हो। विशेष रूप से बेटियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना जरूरी है, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ जीवन जी सकें और किसी भी परिस्थिति में मजबूरी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि समाज में आज भी बेटियों और बेटों के बीच व्यवहार और अवसरों को लेकर अंतर दिखाई देता है। बेटियों को विवाह के बाद नए परिवार में जाना पड़ता है और यदि वहां आर्थिक अभाव की स्थिति हो, तो उन्हें कई बार कठिनाइयों और तानों का सामना करना पड़ता है।

मंत्री पटेल ने भोपाल हाट में 21वें रीजनल सरस मेले का किया शुभारंभ

भोपाल (ब्यूरो)



भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि सरस मेला महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का एक प्रभावी और महत्वपूर्ण मंच है।

यह आयोजन ग्रामीण महिलाओं की उद्यमशीलता को मंच प्रदान करने के साथ-साथ उनके उत्पादों को एक नई पहचान दिलाने, नए बाजार से जोड़ने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सशक्त पहल है। मंत्री श्री पटेल ने भोपाल हाट परिसर में 21वें रीजनल सरस मेला 2026 का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की राज्यमंत्री श्रीमती राधा सिंह भी उपस्थित रहीं। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि भोपाल हाट में यह लगातार 21वां सफल आयोजन है, जो महिला सशक्तिकरण को नई गति दे रहा है। मेला 23 अक्टूबर से 4 नवंबर 2026 तक संचालित रहेगा। मेले म 52 स्व-सहायता समूहों, मध्य प्रदेश के 104 महिला समूहों तथा विकास आयुक्त (हथकरघा) से जुड़े 45 शिल्पियों सहित कुल 201 स्वरोजगारियों ने पंजीयन कराया है।

मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय परिसर में स्वदेशी मेला शुरू

राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा का रक्षा कवच है स्वदेशी : डॉ. सेठी



भोपाल (ब्यूरो)

स्वदेशी केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता का विषय नहीं है, बल्कि यह देश की संप्रभुता और सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। स्वदेशी विदेशी कंपनियों के प्रभाव से देश को बचाने वाला रक्षा कवच है। यह बात स्वदेशी मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि डॉ. राजेश सेठी, सह संघचालक, मध्य भारत प्रांत ने कही। स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वर्गीय भारतवर्ष फाउंडेशन के समन्वय से शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय परिसर, भोपाल में आयोजित मेले का उद्घाटन उत्साह और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच हुआ।

डॉ. सेठी ने कहा कि भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी। उन्होंने समाज से स्वदेशी की भावना को आत्मसात करने और अगले वर्ष इससे भी बड़े मेले के आयोजन का संकल्प लेने का आह्वान किया।

समारोह के विशिष्ट अतिथि एवं भोपाल के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के विधायक भगवानदास सबनानी ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच लंबे समय से स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भारत को विश्वगुरु बनाने के लक्ष्य को गति मिलेगी। मेला संयोजक सतीश विश्वकर्मा ने कहा कि देशभर में लगभग 700 स्वदेशी मेले आयोजित करने की योजना है, जिनमें मध्य प्रदेश में 28 मेले आयोजित किए जाने हैं। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी दर्शकों का मन मोह लिया। गायक अमित शर्मा और सीमा पटेल ने भजनों की प्रस्तुति दी। इसमें फिल्म हनुमान अंश के प्रसिद्ध गीत 'तेरे ही भरोसे हनुमान' सहित अन्य भजन शामिल रहे। वी योग नृत्य अकादमी के बच्चों ने कथक प्रस्तुत किया, जबकि राजस्थानी लोकनृत्य घूमर ने कार्यक्रम में लोकसंस्कृति के रंग बिखेरे।

कार्यक्रम में जितेंद्र गुप्ता, अखिल भारतीय सह समन्वयक, स्वावलम्बी भारत अभियान, सुधीर दाते, मध्य क्षेत्र संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच, श्रीकांत भदौरिया, श्रीमती सीमा भारद्वाज, दीपक वर्मा, रमन तिवारी और विनय कुमार सेनी भी मौजूद रहे।

सच्चे दिन
निडर • निष्पक्ष • निर्भीक
दि डेली हिंदी न्यूज़पेपर | स्थापित 2021
सच्चे दिन अखबार के लिए पत्रकारों की आवश्यकता
मध्य प्रदेश के हर जिले से अनुभवी पत्रकारों की आवश्यकता
आवश्यकता का विवरण
• पद: जिला संवाददाता / क्षेत्रीय पत्रकार
• स्थान: मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में
• अनुभव: पत्रकारिता में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव
• योग्यता: हिंदी में लेखन, रिपोर्टिंग और समाचार संकलन में कुशल
हम क्या चाहते हैं
• स्थानीय समाचारों की सटीक और निष्पक्ष रिपोर्टिंग
• क्षेत्रीय घटनाओं पर गहन कवरेज और विश्लेषण
• डिजिटल/प्रिंट मीडिया में कार्य अनुभव को प्राथमिकता
"जनता की आवाज, जवाबदेह व्यवस्था की पहल"
हमारा उद्देश्य — प्रदेश के हर जिले से जनता की आवाज को सच्चाई और निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत करना
संपर्क करें: 7049734046
आवेदन हेतु संपर्क करें
सोमवार से शनिवार | सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडेटा/प्रोफ़ाइल भेजें:
hr@sachedinnews.in | www.sachedinnews.in
नोट: केवल योग्य और अनुभवी पत्रकार ही संपर्क करें | आवेदन शीघ्र करें

दैनिक सच्चे दिन
वर्ष 6 • अंक 2147 • गुरुवार, 23 सितम्बर 2026
भोपाल बोलेगा, सच्चे दिन छपेगा
सच्ची खबर • जनहित की आवाज
संपर्क: 7049734046
ईमेल: info@dainiksacchedin.in
अपनी खबर भेजें
विश्वसनीय • निष्पक्ष • त्वरित
© दैनिक सच्चे दिन | भोपाल संस्करण | www.dainiksacchedin.in

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक , प्रकाशक **साहबजादा अब्दुल रशीद खान** द्वारा आर.के. एण्ड प्रिंटर्स 7 नीम वाली सड़क जिंसी जहांगीराबाद भोपाल म.प्र.482008 से मुद्रित तथा 424, मेहंदी वालीगली, तलैया भोपाल म.प्र. 462001 से प्रकाशित।
सम्पादक- अज़रा बैगम (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल न्यायालय रहेगा।) RNI No. MPHIN/2021/82412